

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com



फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371 वर्ष: 46 संख्या: 292 प्रभात बीकानेर, गुरुवार 15 मई, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 ₹.

‘बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान से अलग देश घोषित किया

बलूच प्रतिनिधि मीर यार बलोच ने एक्स पर यह घोषणा करते हुए विश्व से अपील की कि अब ‘‘शांत’’ रहने का समय नहीं है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 मई। बलूचप्रतिनिधि मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित कर दिया है, उन्होंने इस घोषणा का कारण क्षेत्र में दशकों से जारी भारी हिंसा, जबरदस्ती लोगों को उठा ले जाने और मानवाधिकार हनन को बताया।

उन्होंने कहा, ‘‘तुम मारोगे, हम निकलेंगे। हम नस्ल बचाने निकले हैं। आओ, हमारा साथ दो। पाकिस्तान अधिकृत बलूचिस्तान के बलोच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और अब दुनिया सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती।’’

भारतीय नागरिकों, खासकर मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से उन्होंने अनुरोध किया कि वे बलूचों को ‘‘पाकिस्तान के अपने लोग’’ कहना बंद करें।

उन्होंने कहा, ‘‘बलूच नैरेटिव !!प्रिय भारतीय राष्ट्रवादी मीडिया, यू ट्यूब सथी और भारत के बचाव में लगे बुद्धिजीवियों से अनुरोध है कि बलूचों को ‘‘पाकिस्तान के अपने लोग’’ न कहें। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के असली अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्हें

■ हालांकि, पाकिस्तान से अलग देश होने के बलूच निवासियों के इस प्रयास को पूर्ण सफलता मिलना कोई आसान काम नहीं है, पर, मीर यार बलोच की विश्व से अपील काफी मार्मिक है।

■ स्वतंत्र होने की इस घोषणा के साथ, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी रिलीज़ की, जो ‘‘बलूचिस्तान’’ के निवासियों के मुंह जुबानी बयानों पर आधारित है।

■ डॉक्यूमेंट्री के अनुसार, दशकों से, ‘‘बलूचिस्तान’’ विश्व की दृष्टि से ओझल सा रहा है। हालांकि, ‘‘बलूचिस्तान’’ में प्राकृतिक संपदा तथा बेशकीमती खनिजों का भंडार है, पर, फिर भी यह क्षेत्र सदा पाकिस्तान के शासकों के रडार पर नहीं आ पाया। अब तक इस अवहेलना के कारण, स्वायत्तता व पहचान के लिये संघर्ष करता रहा है।

कभी भी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा।’’

मीर यार बलोच ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) पर भारत के रुख का पूरा समर्थन भी किया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर उस क्षेत्र को खाली करने का दबाव बनाने की अपील की।

इसी बीच, एक नई डॉक्यूमेंट्री

‘‘बलूचिस्तान: द लॉन्ग रोड टू रैज़िस्टेंस’’ भी ध्यान आकर्षित कर रही है। यह फिल्म बलूच नागरिकों के वास्तविक अनुभवों को गहराई से दिखाती है, जिनकी आवाजें लंबे समय से दमन के कारण खामोश थीं।

बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का

सबसे बड़ा और सबसे उपेक्षित प्रांत है, दशकों से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान से वर्चित रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद, यह क्षेत्र गरीबी से त्रस्त है और

लंबे समय से स्वतंत्रता और पहचान की लड़ाई लड़ रहा है।

जबरन गायब कर देना, हिरासत में यातना, गैर-व्याधिक हत्याएं और मीडिया पर सेंसरशिप- बलूच लोगों ने इन सबका सामना किया है। इनमें से कई घटनाएं तो सामने भी नहीं आई हैं। पीड़ितों, गुमशुदा लोगों के परिवारों और कार्यकर्ताओं की गवाही इस संगठित दमन की डरावनी सच्चाई को उजागर करती है।

यह फिल्म भारत की ओर से ‘‘ऑपरेशन सिंदूर’’ (पहलगाम नरसंहार के जवाब में की गई कार्रवाई) के बाद रिलीज़ हुई है। यह याद दिलाती है कि जब दुनिया की सुर्खियां सीमा पार आतंक पर केन्द्रित होती हैं, तब पाकिस्तान को अपनी सीमाओं के भीतर एक मौन युद्ध जारी रहता है।

बलूच नेता की इस घोषणा ने पाकिस्तान के सामने एक नया रणनीतिक संकट खड़ा कर दिया है, जो पहले से ही कई मोर्चों पर जुझ रहा है। आज की यह घोषणा भारत को एक राजनयिक हथियार देती है, जिससे पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जा सकता है।

हालांकि बलूच लोगों के लिए पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करना आसान नहीं होगा, फिर भी यह घटनाक्रम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिना विभागीय जाँच के कर्मचारी को बर्खास्त नहीं कर सकते

जयपुर, 14 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना विभागीय जांच के, केवल एफआईआर के आधार पर कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता कॉन्स्टेबल को बिना जांच ही सेवा से बर्खास्त करने

■ हाई कोर्ट ने केवल एफआईआर के आधार पर सेवा से बर्खास्त करने को अवैध करार दिया तथा सभी सेवा परिलाभ के साथ बहाल करने का आदेश दिया।

वाले पुलिस विभाग के आदेश को मनमाना व अवैध करार देते हुए उसे सभी सेवा परिलाभ सहित सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपीलैट अधीार्टी के आदेश को भी रद्द करते हुए कहा कि वह अपील में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने में फेल रहा है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्तों को आजीवन कारावास

जयपुर, 14 मई। पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग को होटल में बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मोनू उर्फ मोईन खान और श्रवण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पीठासीन अधिकारी राजवीर सिंह ने दोनों अभियुक्तों पर कुल 1.04 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार जाटावत और पीडित पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुणाल शर्मा ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता ने 15 अगस्त,

■ पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 15 अगस्त 2023 को दर्ज मामले में फैसला सुनाया।

2023 को जालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी अपने पिता से किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह बात उसकी बहन को पता चलने पर वह उसे जयपुर ले आई और होटल में दो दिन साथ रहीं। इस दौरान, उसकी बहन ने मोनू से, अपना धर्म का भाई बताकर, मिलाया। इसके बाद उसकी बहन उसे वहां यह कहकर छोड़ गई कि मोनू उसका ध्यान रखेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि बहन के जाते ही मोनू ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बंधक बना लिया। अभियुक्त मोनू रोज रात को आता और उसके साथ दुष्कर्म करता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बुधवार को कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की

बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर प्र.मंत्री मोदी से पूछा कि वे इतने चुप और शांत क्यों हैं?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 मई। क्या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी की स्थिति अयुक्तियुक्त (अनटैनेबल) हो रही है?

यह प्रश्न संघ परिवार के अंदर विभिन्न स्तरों पर पूछा जा रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक तथ्य यह है कि यह सवाल दिल्ली में स्थित विदेश राजनयिकों के बीच भी सुनाई दे रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के परिप्रेश्य में आमतौर से मोदी जी के भविष्य के बारे में चिंतन करते रहते हैं।

आरएसएस यह प्रश्न कर रही है कि आखिर मोदी अपने अपमान पर चुप क्यों हैं, जबकि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने मोदी के खिलाफ बयान दिये हैं तथा डंके की चोट पर यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि नरेन्द्र मोदी अमेरिका के दबाव के आगे झुक गये और युद्धविराम के लिये सहमत हो गये, जबकि सैन्य स्थिति भारत के लिये बहुत अच्छी थी तथा देश युद्ध में विजय के नजदीक था। कांग्रेस ने आज शाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की एक और

■ सर्वदलीय बैठक बुलाकर विपक्ष से ‘‘शेयर’’ क्यों नहीं करते, पहलगाम की घटना का विवरण और उसके बाद का घटनाक्रम।

■ जैसा कि विदित ही है, 25 मई को प्र.मंत्री मोदी ने एनडीए के मु.मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। अतः सीडब्ल्युसी की बैठक के प्रस्ताव के जरिए विपक्ष यह सवाल उठा रहा है कि एनडीए के मु.मंत्रियों की बैठक के लिये तो प्र.मंत्री के पास समय है, पर, सर्वदलीय बैठक के लिये क्यों नहीं?

■ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सीडब्ल्युसी की बैठक के बाद टिप्पणी की कि नह्ना जीवनपर्यंत भाजपा अध्यक्ष नहीं रह सकते, अतः उनके स्थान पर नया अध्यक्ष बनने के बाद, प्र.मंत्री मोदी का क्या होगा?

मीटिंग बुलाई तथा उसमें एक प्रस्ताव पारित कर मोदी से पूछा है कि वे खामोश क्यों हैं तथा कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, वे कहाँ हैं? कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिये तथा सबको जानकारी देनी चाहिये। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री मोदी पिछली

दो मीटिंगों में उपस्थित नहीं हुये हैं। कांग्रेस यह भी कह रही है कि सरकार, भारत और पाकिस्तान को बराबर के स्तर पर रखे जाने पर आपत्ति नहीं जता रही है। कांग्रेस ने यह जानना चाहा है कि क्या यह स्थिति (दोनों देशों को बराबर के स्तर पर रखा जाना) मोदी जी को स्वीकार्य है? (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से व्यापारिक संबंध समाप्त किये

व्यापारियों में गहरा आक्रोश है कि तुर्की आतंकवाद का समर्थन करने वाले पाकिस्तान का साथ दे रहा है

उदयपुर, 14 मई (कासं)। भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्किये द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने पर उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने राष्ट्र हित में तुर्किये के साथ सभी व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है।

उदयपुर मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गंगावत ने बताया कि हालांकि तुर्किये के साथ उनके पुराने और अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं और बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट मार्बल का आयात किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यापार जारी नहीं रखा जा सकता। व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि ‘दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है’ और उनके लिए व्यापारिक हिताों से पहले देश का हित महत्वपूर्ण है। व्यापारी समुदाय में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि तुर्किये भारत के खिलाफ आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान का साथ दे रहा है। गंगावत ने बताया कि तुर्किये से हमारे

■ मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि तुर्की से हर साल बड़ी तादाद में ग्रेनाइट व मार्बल का आयात किया जाता है। उन्होंने कहा, उनके लिये व्यापारिक हित से पहले देश हित है।

व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे हैं, जिस कारण काफी मार्बल व्यापारी तुर्किये से ग्रेनाइट मार्बल का आयात करते हैं। तुर्की इसको नजरअंदाज करते हुए हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को सहयोग कर रहा है। इससे हमारे मार्बल व्यापारियों में बहुत ही आक्रोश है। गंगावत बताते हैं कि तुर्किये से हर साल बड़ी तादाद में ग्रेनाइट मार्बल

आयात किया जाता है, जो कि वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीयता के खिलाफ है। गंगावत ने तो सरकार से कहा कि तुर्किये के साथ मार्बल व्यापार को पूरे देश में प्रतिबंधित करें। व्यापारिक प्रतिबंध के साथ ही पर्यटन को भी बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि मेवाड़ में उदयपुर मार्बल व्यवसाय का बड़ा हब है और यहां तुर्किये से हजारों टन मार्बल आयात किया जाता है, ऐसे में उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के सदस्यों ने बड़ा निर्णय लेते हुए तुर्किये से मार्बल आयात करने का बहिष्कार शुरू किया है।

उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति के अध्यक्ष कपिल सुराणा कहते हैं कि हमने तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पत्र लिखकर तुर्किये से सभी व्यापारिक रिश्ते तोड़ने की मांग की है। वे बताते हैं कि फिलहाल पूरे देश में जितना मार्बल आयात किया जाता है, उसका 70 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ तुर्किये से आयात (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 मई। युद्धविराम -

विवाद, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच शांतिदूत बनने के अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के दावे ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, के बीच, चीन और बाँग्लादेश भारत के पूर्व के सीमावर्ती राज्यों में परेशानी खड़ी करते प्रतीत हो रहे हैं।

बताया जाता है कि चीन ने अरुणाचल के बहुत से स्थानों के नये नाम रख दिये हैं। भारत ने चीन की इस गतिविधि को ‘‘निरर्थक एवं हास्यास्पद’’ करार दिया है, जिससे सम्बंधित क्षेत्र के भारत का अभिन्न हिस्सा होने की स्थिति (स्टेटस) बदलने वाली नहीं है।

चीन ने दावा किया कि अरुणाचल ‘‘दक्षिणी तिब्बत’’ है। उसने हाल ही में भारतीय राज्य अरुणाचल के विभिन्न स्थानों के नामों की एक सूची जारी की है। इसकी प्रतिक्रिया में, भारत के विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान जारी किया,

चीन ने अरुणाचल के कई स्थानों को नया नाम देना शुरू किया तथा इस क्षेत्र को ‘‘दक्षिण तिब्बत’’ बताया

■ दूसरी ओर, बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद युनुस ने भी बाँग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा नॉर्थ ईस्ट के सात राज्यों के लिये ‘‘इकोनॉमिक प्लान’’ का प्रस्ताव रखा है।

■ पिछले दिनों, युनुस ने चीन यात्रा के दौरान टिप्पणी की थी कि नॉर्थ ईस्ट, ‘‘लैण्ड लॉक्ड’’ है तथा समुद्र तक पहुँचने का इस राज्य के पास कोई रास्ता नहीं है। अतः इस क्षेत्र के लोगों को आपस में मिलकर, माल बनाना चाहिये जो चीन को बेचा जायेगा।

जिसमें कहा गया कि ‘‘इन स्थानों को नये नाम देने से यह अकाट्य वास्तविकता, जो संदेह से परे है, नहीं बदलेगी कि अरुणाचल भारत का अभिन्न एवं अहस्तान्तरणीय हिस्सा था, है और सदैव रहेगा।

दूसरी ओर, मोहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अन्तरिम बाँग्लादेश सरकार ने एक बार फिर बेसुरा राग अलापते हुये, एक व्यापक आर्थिक एकीकरण योजना प्रस्तावित की है, जिसमें बाँग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा

भारत के सात उत्तर -पूर्वी राज्य सम्मिलित किये गये हैं। गौरतलब बात यह है कि युनुस ने इसमें भारत का जिक्र न करते हुये, केवल पूर्वोत्तर राज्यों का ही उल्लेख किया है। कुछ दिन पहले, अपनी चीन यात्रा के दौरान, यूनुस ने बाँग्लादेश को उत्पादन, लॉजिस्टिक्स तथा व्यापार के क्षेत्र में चीन के प्रमुख क्षेत्रीय पार्टनर के रुप में प्रस्तुत कर दिया था, तथा भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को ‘‘लैन्डलॉक्ड’’ (जमीन से घिरे हुये) करार दिया था। बाँग्लादेश में चीन को

अत्यधिक निवेश के लिये आमंत्रित करते हुये, युनुस ने अपने देश को ‘‘महासागर का एकमात्र अभिभावक’’ बताया था। इस पृष्ठभूमि में देखने पर, जो इस समय बाँग्लादेश की यात्रा पर आये हुये हैं। युनुस ने हाइड्रोपावर, हैल्युकेयर तथा ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सीमा-पार के सहयोग (क्रॉस बॉर्डर कॉलिबोरेशन) को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस सैक्टर से सम्बंधित सामान संयुक्त रुप से बाँग्लादेश में निर्मित किया जाये तथा चीन को बेच दिया जाये।

अर्थशास्त्री तथा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, संजीव सान्याल ने यूनुस द्वारा चीन से की गई इस आर्थिक अपील में भारत के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पाकिस्तान रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को छोड़ा

नयी दिल्ली, 14 मई। पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान पूर्णम कुमार शॉ को छोड़ दिया है।

शॉ 20 दिन से पाकिस्तान रेंजर्स के कब्जे में थे। बीएसएफ ने बुधवार को प्रेस विज्ञापन जारी कर कहा, आज सुबह 10.30 बजे कांस्टेबल पूर्णम कुमार शॉ को अटारी-वाघा सीमा पर बीएसएफ

■ सीमा सुरक्षा बल का जवान पूर्णम कुमार शॉ गत 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान सीमा में चला गया था।

द्वारा पाकिस्तान से वापस लाया गया। विज्ञित के अनुसार, शॉ 23 अप्रैल 2025 को लगभग 11.50 बजे फिरोजपुर सेक्टर में ऑपरेशनल ड्यूटी पर रहते हुए अज्ञान में पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और उन्हे पाक रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया था। विज्ञित में कहा गया है कि पाकिस्तान रेंजर्स के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 14 मई। कैनडा की नई विदेश मंत्री के रूप में अनिता आनंद की नियुक्ति देश की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है - विशेष रूप से भारत के साथ बेहद तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में। आनंद, जो कि दूसरी पीढ़ी की भारतीय मूल की कैनडा नागरिक हैं, ने भागवद् गीता पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। यह प्रतीकात्मक इशारा एक शक्तिशाली संदेश देता है: कैनडा की यह शीर्ष राजनयिक कैनडा और भारत, दोनों पहचानों से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

यह दोहरी विरासत उसे समय में एक राजनयिक सेतु के रूप में कार्य कर सकती है, जब दोनों देशों को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

सन् 2023 में कैनडा-भारत संबंध उस समय सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, जब टूटो सरकार ने

भारतीय एजेंसियों पर, कैनडा के सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कथित संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए। इसके परिणाम तुरंत सामने आए: राजनयिक निष्कासन, व्यापार वार्ताओं का ठप्प होना और वीजा सेवाओं पर रोक। कई महीनों तक संवाद बंद रहा और गतिरोध बना रहा। अनिता आनंद का विदेश मंत्री बनना ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देशों को राजनयिक संबंधों में सुधार से लाभ मिल सकता है। आनंद की भारतीय विरासत केवल प्रतीकात्मक नहीं है, यह पहचान उन्हें भारत की वैश्विक स्थिति के पीछे की सांस्कृतिक और राजनीतिक संवेदनाओं की स्वाभाविक समझ देती

■ अनिता आनन्द ने गीता पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली और अपने भारतीय मूल पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया

■ पर, कैनडा-भारत रिश्ते, जो पिछली दूढ़ो सरकार के ‘‘खालिस्तानी समर्थक’’ रूख के कारण काफी कटू हो गये थे और विशेषकर, हरदीप सिंह निज्ज़र की हत्या के बाद कटुता काफी बढी थी, क्या, अब रिश्ते सामान्य होंगे।

■ यह भी सच है कि चौदह लाख भारतीय मूल के कैनडा वासियों में काफी मतभेद हैं, खालिस्तानियों की गतिविधियों के कारण। यह मतभेद अचानक खत्म नहीं हो जायेंगे, अनिता आनन्द के आने से, पर, रिश्तों में तनाव काफी कम हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा, नई सरकार में अनिता आनन्द को कितना लचीलापन मिलता है, दोनों की सोच व विचारों में कुछ सामंजस्य बिठाने के लिये।

है। साथ ही, इस पहचान के कारण, प्रवासी समुदाय में उग्रवाद जैसे मुद्दों पर

शांति से बातचीत करने के लिए उन्हें एक अनूठी मिली है। यह मुद्दा द्विपक्षीय

संबंधों में एक बड़ा अवरोध रहा है। कैनडा की पूर्व लिबरल सरकार के

एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व आईएसस संधू की ओर से बहस

जयपुर, 14 मई। राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को एकल पट्टा प्रकरण को लेकर सुनवाई हुई। पूर्व आईएसएस जीएस संधू की ओर से मामले में अपना पक्ष रखा गया। वहीं, अदालत ने मामले में गुरुवार को सुनवाई जारी रखना तय किया है। चीफ जस्टिस एमएम

■ संधु की ओर से दलील दी गई कि एकल पट्टा निरस्त होने के बाद एसीबी में शिकायत की गई, जबकि कोई अपराध नहीं बनता है।

श्रीवास्तव की एकलपीठ ने ये आदेश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, जीएस संधू, निष्काम दिवाकर और ओंकार मल सैनी की ओर से दायर सात आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान, संधु की ओर से अधिवक्ता एसएस होरा ने पक्ष रखा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK



CMYK

विचार बिन्दु

हमारी आनंदपूर्ण बदकारियाँ ही हमारी उपीड़क चाबुक बन जाती हैं। –शेक्सपियर

जाति जनगणना से इतना क्या डरना

भारत के लिए जाति कोई नई बात नहीं।भारतीय समाज जाति विहीन समाज कभी नहीं रहा। पहले इसे वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना गया और कालांतर में यह जन्म से जुड़ गई। जो कुम्हार, खाली, नाई के घर पैदा हुआ सो ता जिंदगी कुम्हार, खाली, नाई चाहे उसे कुम्हारी, खाली, नाईगीरी का काम उसकी रूचि का हो या न हो, आए या न आए। जो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ सो ब्राह्मण चाहे उसे शास्त्रों का कक्का भी न आए। सैद्धांतिक तौर पर यह पढ़ाया जाता

रहा है कि कर्म से वर्ण परिवर्तन सम्भव था किंतु हमारे देश में , शायद वास्तविकता में यह कभी सम्भव नहीं था।

ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न कारणों से और मुख्यतः भारतीय समाज के गहरे बिखराव-असमानता-जाती के आधार पर भेदभाव-छुआछूत आदि को उभार कर समाज को और विभाजित करने के लिए जाती जनगणना को हथियार बनाया। बहुत से शासक, समाज विद्विष मुर्खों पर बंट कर राज करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं।

ब्रिटिशर्स द्वारा प्रथम बार 1881 में जनगणना करवाई। मुख्य मुख्य जातियों के आंकड़े भी इकट्ठे करने का प्रयास किया। 1931 की जनगणना में जाति के आंकड़े शामिल थे। कुल जनसंख्या लगभग 27 करोड़ थी। इस जनसंख्या में से, काका कालेलकर आयोग द्वारा चिन्हित जातियों की जनसंख्या, अनुमानतः, 52% बनती थी। तत्समय भी, कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों ने, दबे स्वरों में जातीय जनगणना का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे जातिगत विभाजन बढ़ेगा और सामाजिक तनाव पैदा होगा।

जातीय जनगणना के मुद्दे पर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के विचार और रुख समय-समय पर बदलते रहे हैं। कुछ लोगों ने जातीय जनगणना का समर्थन किया, कुछ ने विरोध किया। यह मुद्दा अभी भी बहस का विषय है। जातीय जनगणना के संबंध में कुछ प्रमुख व्यक्तियों, संगठनों के विचार इस प्रकार रहे हैं:—

महात्मा गांधी जाति प्रथा के उन्मूलन और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। उन्होंने जाति प्रथा को एक सामाजिक बुराई माना और इसके खिलाफ काम किया। वे जातीय जनगणना के पक्ष में थे या नहीं यह स्पष्ट नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने भी जाति प्रथा के उन्मूलन और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उन्होंने जाति प्रथा को एक सामाजिक बाधा माना। इसके खिलाफ काम किया।

नेहरू जी ने 1951 की जनगणना में एन.ए.ए. के अतिरिक्त अन्य जातियों के आंकड़े इकट्ठा नहीं करने के निर्णय का समर्थन किया। शायद सरकार को आशा रही होगी कि जातिगत विभाजन धीरे-धीरे स्वतः कम होगा, अधिक समतापूर्ण समाज बन जाएगा किन्तु यह आशा फीकीभूत नहीं हुई।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने जाति प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए काम किया। उन्होंने जाति प्रथा को एक बड़ी सामाजिक बुराई माना। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रारण्यों की मांग की। उन्होंने जातीय जनगणना को दलित समुदाय की स्थिति को समझने और उनके लिए नीतियां बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन माना। इन तीनों नेताओं के विचारों में समानता थी कि वे जाति प्रथा को एक बड़ी सामाजिक बुराई मानते थे और उसके उन्मूलन और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के पक्षधर थे।

हिंदुत्व व हिन्दू वादी कुछ लोग व संगठन जातीय जनगणना का लगातार विरोध करते रहे हैं। उनके अनुसार जातीय जनगणना से जातिगत विभाजन बढ़ेगा, सामाजिक ताना बाना टूटेगा, तनाव पैदा होगा। सामाजिक समरसता एकता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए जातीय जनगणना को अनावश्यक मानते थे और अब भी मानते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख काफी समय दुर्लभिल व अस्पष्ट रहा किन्तु कुछ समय से कांग्रेस पार्टी ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर अपने रुख को स्पष्ट किया है। अब, वह इसके पक्ष में है। समाजिक न्याय की वकालत करने वाली, समाजवादी, साम्यवादी विचारधाराओं से जुड़ी पार्टियां जातीय जनगणना का समर्थन करती रही हैं और अब भी करती हैं। बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में जातीय आंकड़े (सर्वे) इक्कठे करने का राज्य स्तर पर प्रयास किया गया। सँविधान के अनुसार जनगणना हो या जातीय जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार का।

आजाद भारत में, पिछड़ी जातियों की दैन्यीय शैक्षणिक व सामाजिक को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों सुझाव देने के लिए, 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर आयोग का गठन किया। इसकी रिपोर्ट 1955 में आई थी। इस आयोग को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है। प्रसिद्ध गांधीवादी काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग ने पिछड़ी जातियों की परचान कर उनकी सूची बनाई। इसमें कुछ जातियों को अति पिछड़ा भी माना। इन के सदस्यों ने जाति को छिछोरेपन से जोड़ने या नौकरियों में इन्के लिए स्थान सुनिश्चित करने के मुद्दे पर एक राय नहीं थी। प्रश्न था की क्या केवल जाति से ही पिछड़ापन तय किया जाए? जाति को बैकवाटनेस का मानदंड मानने के पक्ष में भी कुछ सदस्य थे।

आयोग की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार का मोटा-मोटा रुख यह रहा कि पिछड़ी जातियों को चिन्हित करने का कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड तय नहीं आ पाया। इसलिए इस आयोग की रिपोर्ट कि अधिकांश सिफारिशें सरकारी फाइलों में दफन रही। आयोग ने पिछड़ी जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नति के लिए कुछ सिफारिशें भी दी।

समय-समय पर, विभिन्न सरकारों यथा बिहार की कर्पूरी ठाकुर व यूपी की राम नरेश यादव सरकार ने नौकरियों में आरक्षण देने की पहल भी की। कालेलकर आयोग के प्रतिवेदन को ध्यान में रख कर ही जनता पार्टी सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। देर से ही सही, मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियावयन की भी धीमी कार्यवाही शुरू हुई। संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुसार राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार है, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन

सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान को सार रूप में 1990 तक लागू नहीं किया गया।

वर्ष 2011 में केंद्र की व्डी सरकार ने सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से कमजोर जातियों (SEC) का सर्वे जरूर करवाया किन्तु आंकड़े सार्वजनिक कर पाती उस से पहले ही UPA सरकार 2014 में सत्ता से बाहर हो गई। 2014 के बाद से लगातार सत्ता में रहने वाली वर्तमान सरकार ने, विभिन्न राजनीतिक व मिथ्या सैद्धांतिक बहानों के आधार पर इन्हें सार्वजनिक नहीं किया।

1980-90 तक आरक्षण की स्थिति?

आजादी के समय छँ की आबादी मुख्य रूप से गांवों में रहती थी। भारत की स्वतंत्रता के समय गांवों में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? यह सर्वविदित है। 1980-85 से पहले सरकारी नौकरियों में OBC का प्रतिनिधित्व नगण्य था। जो था वह भी अधिकांशतः चपरासी, लिपिक, अघ्यापक, समकक्ष अन्य श्रेणियों तक ही सीमित था। बड़े पदों पर तो केवल गिने-चुने आर्थिक रूप से सक्षम घरों के इक्के-दुक्के लोग ही आ पाते थे। 1990 तक के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट: सिद्ध है। OBCका दूसरा पहलू यह है कि 1985-90 से पूर्व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ओबीसी के युवक बड़े पदों के लिए उपयुक्त योग्यता ही नहीं पा सके थे। लगभग 65-70% ऊंचे पदों वाली नौकरियों पर सवर्ण वर्ग के लोगों का ही बोलबाला था।

1990 में मंडल सिफारिशों को लागू करने की मांग जोरों से उठने लगी। नौकरियों में आरक्षण के कारण सवर्ण वर्गों के लोगों को नौकरियों में अपना वर्चस्व समाप्त होते दिखा तो कुछ राजनीतिक दलों, संगठनों ने उनके इस डर को हवा दी और छँ आरक्षण के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा कर दिया जो कालांतर में हिंसक भी हुआ।

अब देर से ही सही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगामी जनगणना में जातीय जनगणना करने का निर्णय लिया है। कुछ अनुदारवादी व्यक्तीकृत हिन्दू संगठनों ने भी लगभग 180 डिग्री की पलटी मारकर, जातीय जनगणना के फासले के प्रति सहमति सी प्राप्त की है यद्यपि साथ में यह भी कहा कि इसके आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाए। ऐसापे नियों में उपयोग न हो जिनसे समाज की समरसता खत्म हो। उनका उपयोग केवल नीतिगत निर्णयों में ही हो।

इस प्रकार के 180 डिग्री घाते उलटफेर से पहले भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह, स्व.गोपास मुंडे जैसे कुछ बड़े नेताओं को छोड़ कर अधिकतर नेता जातीय जनगणना का पानी पी-पी कर विरोध करते थे। अब ऐसे अधिकतर नेता समर्थन करने की होड़ में लाग्ए हैं। खैर पुनीत बात है न, बंदरों की तो, मालिक लोग जैसा नाच सिखाएंगे, वैसे नाच लेंगे।

लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर कुछ नए प्रश्न भी उभरे हैं। उनके उत्तर क्या होंगे, उनसे ही पता चलेगा कि इस फैसले के पीछे असली मकसद क्या है? क्या यह केवल और केवल वोटर्स को अपनी ओर लुभाने के लिए ही है ? क्या जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, पिछड़े वर्गों के लोगों की समाजिक, शैक्षणिक व मालिहालत सुधारने के लिए कुछ ठोस निर्णय, योजनाएं बनेंगी और लागू होंगी?

जनगणना अप्रैल 2026 से प्रारम्भ होगी। उस से पहले होगा बिहार विधान सभा के चुनाव। एक परिदृश्य की कल्पना करो कि बिहार में भाजपा को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिलता। भाजपा के वोट बैंक में उसके पारम्परिक वोट बैंक के अतिरिक्त OBC व OBC में बहुत पिछड़े वर्ग के वोट बड़ी संख्या में नही जुड़ते है तो भी, क्या जातियों की गणना कराएंगी, केंद्र सरकार?

एक अन्य बड़ा प्रश्न है, जातियों की गणना करने से सम्बंधित प्रश्न कैसा होगा, क्या-क्या सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी? अभी तो किसी कोने से आवाज निकल रही है, सुझाव आ रहा है कि कोई अलग प्रश्न की आवश्यकता नहीं। वर्तमान प्रश्न पर्याप्त है, उसी में एक कालम जाती का भी हो जाएगा या SC/ST वाले कलम में /OBC और जोड़ दिया जाए लेकिन ऐसा किया जाएगा तो फिर इस गणना का संख्या जानने के अतिरिक्त कोई उपयोगिता नहीं रहेगी।

जाति जनगणना के साथ साथ सम्बंधित व्यक्तियों की शैक्षणिक, वित्तीय स्थितियों यथा घर, वाहन, नौकरी, व्यापार या स्वरोजगार या निर्यामित नौकरी या दिहाड़ी वर्कर, औसत मासिक रोजगार के दिन, वेतन या आमदनी, बैंक से लेनदेन, साहूकार या बैंक से कर्ज, स्वयम की संचित पूंजी, कृषि या अन्य इसी प्रकार की भूमि की जानकारीया एकत्रित करने से ही इस बड़ी एक्ससाइज का कोई उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार की जानकारीयों के अध्ययन, विश्लेषण के उपरांत ही सम्बंधित वर्गों के लिए क्या जातियों के अंदर उपजातियों की गणना की जाएगी और अगर ऐसा किया जाएगा तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या होगा?? समाजों को जातियों के बजाय उपजातियों में और विभाजित कर उनकी राजनीतिक हैसियत, उपयोगिता को कम से कमतर करने के लिए?? यह भी ध्यान रखना होगा कि उपजातियां तथाकथित सवर्ण जातियों में भी हैं।

एक ओर बड़ा प्रश्न है—क्या धार्मिक समूहों यथा मुसलमान, ईसाई, सिख आदि में भी जाती-उपजाती पृष्टी जाएगी? इस्लाम, ईसाई आदि में तो सैद्धांतिक आधार पर तो जाती प्रथा मानी नहीं जाती, तो फिर इसका उपयोग क्या होगा? क्या इससे इन धर्मों में पिछड़ों, अति पिछड़ों की पहचान कर उनके लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में दाखिले आदि में इन आंकड़ों का उपयोग होगा? क्या यह संविधान सम्मत होगा या फिर इनके लिए संविधान में संसोधन होगा, जिसका वर्तमान सरकार वाला दल पुर्जोर विरोध करता है??

एक ओर बड़ा प्रश्न है कि क्या जाती जनगणना के पश्चात, इसके आंकड़ों के आधार पर, OBC वर्ग के लिये सरकारी नौकरियों की उपलब्धता में कोई परिवर्तन किया जाएगा? क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई आरक्षण की 50% की सीमा को बदल कर पिछड़ों की जनसँख्यानुसार नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों दाखिलों की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का साहस सरकार करेगी?? वैसे 50% आरक्षण सीमा सार रूप से, EWS के लिए 10% आरक्षण के बाद समाप्त सी ही तो है। हाँ, EWS आरक्षण के बाद सवर्ण वर्ग के लिए स्वतः 60% का आरक्षण हो गया क्योंकि वर्ग में शामिल नहीं है।

क्या जातियों की जनगणना से सम्बंधित प्रश्न सार्वजनिक होगा? क्या इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा होगी?? और अंत में क्या सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार में जाती/वर्ग आधारित आरक्षण लागू करेगी, जैसी कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों की मांग है???

—अतिथि सम्पादक,

महावीर सिंह,

आई.ए.एस. (से.नि.)



अशोक कुमार

हेल्थ ईज वेल्थ का हिन्दी में मतलब ‘स्वास्थ्य ही धन है’ होता है जिसे ‘नेक तंदुरुस्ती लाख नियामत’ भी कहा जाता है जिसका मतलब है – अच्छा स्वास्थ्य हमेशा धन से ऊपर होता है। वाक्यांश हेल्थ ईज वेल्थ का गहरा अर्थ है और यह हमारे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, और यह कि अच्छा स्वास्थ्य जीवन में सफलता और खुशी का आधार है। सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत में खाने में प्रयोग होने वाली कई ऐसी चीजें हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है या उपयोग को सीमित किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख वस्तुएँ इस प्रकार हैं: कुछ सिंथेटिक रंगा. उच्च सोडियम वाले जंक फूड, कुछ कीटनाशक जैसे एलिड्न, डीडीटी, एंडोसल्फान आदि, कुछ कृत्रिम स्वीटनर, तंबाकू और निकोटीन: किसी भी खाद्य पदार्थ में इनका उपयोग प्रतिबंधित, कुछ कृत्रिम स्वीटनर, सैसाफ्रास ऑयल, ब्रॉमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, दवाओं पर प्रतिबंध, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (एफडीडी) दवाएं, कुछ दर्द निवारक दवाएं, कुछ एंटी-एलर्जिक दवाएं जैसे ब्रोमेलैटिन, प्रोटोएज, कुछ सिंगल यूज्ड माइक्रो प्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स आदि प्रतिबंधित हैं।

सिगरेट और तंबाकू से होने वाली कुल मौतों में यकृत कैंसर का विशिष्ट प्रतिशत बताना संभव नहीं है, यह स्पष्ट है कि तंबाकू का उपयोग यकृत कैंसर के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक

है और भारत में होने वाली लाखों तंबाकू-संबंधी मौतों में योगदान देता है। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास और जागरूकता बढ़ाना इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। उपलब्ध आंकड़ों और हालिया घटनाओं को देखते हुए, यह कहना सुरक्षित है कि पिछले 5 वर्षों में भारत में कच्ची या जहरीली शराब के सेवन से हजारों लोगों की मौत हुई है। सरकारी आंकड़े केवल 2020 तक के हैं, और उसके बाद भी कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आंकड़े संभवतः कम करके आंके गए हैं, क्योंकि कई मौतें रिपोर्ट नहीं की जाती हैं। कच्ची शराब का अवैध उत्पादन और बिक्री एक गंभीर समस्या बनी हुई है, खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में। शराबबंदी के आर्थिक प्रभाव जटिल हो सकते हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना, कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि शराबबंदी से राजस्व में कमी आ सकती है और अवैध शराब के व्यापार में वृद्धि हो सकती है, जबकि अन्य अध्ययनों में सकारात्मक सामाजिक और स्वास्थ्य परिणाम देखे गए हैं।

हानिकारक उत्पादों से राजस्व अर्जित करके अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए धन जुटा रही है, जबकि इन उत्पादों का सेवन स्वयं ही स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। कई लोग यह मानते हैं कि सरकार को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक स्वस्थ आबादी अंततः अधिक खुशहाल और अधिक उत्पादक होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। राजस्व के अन्य स्थायी और स्वास्थ्यकर स्रोत खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

यह कहना सही होगा कि राजस्व एक महत्वपूर्ण कामक है जो सरकार के फैसलों को प्रभावित करता है। इन उत्पादों पर लगाए गए टैक्स सरकार के लिए आय का एक बड़ा स्रोत होते हैं, जिसका इस्तेमाल विभिन्न विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। अगर सरकार अचानक से इनका उत्पादन बंद कर दे, तो उसे एक बड़े राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिससे अन्य जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, यह कहना कि सरकार को सिर्फ राजस्व का ध्यान रहता है और स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, पूरी तरह

वित्तीय और नैतिक विचारों के बीच एक जटिल खींचतान है। सरकार

का तर्क अक्सर यह होता है कि उस राजस्व का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा (हानिकारक उत्पादों से होने वाली बीमारियों के इलाज सहित), बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। उनका यह भी कहना हो सकता है कि पूर्ण प्रतिबंध से अवैध व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होगा और गुणवत्ता नियंत्रण भी नहीं रहेगा।

हालांकि, एक स्वस्थ आबादी किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हानिकारक उत्पादों से होने वाली बीमारियों का बोझ न केवल व्यक्तियों और उनके परिवारों पर पड़ता है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भी भारी दबाव डालता है और देश की समग्र उत्पादकता को कम करता है।

सरकार हानिकारक उत्पादों से राजस्व अर्जित करके अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए धन जुटा रही है, जबकि इन उत्पादों का सेवन स्वयं ही स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।

कई लोग यह मानते हैं कि सरकार को दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एक स्वस्थ आबादी अंततः अधिक खुशहाल और अधिक उत्पादक होगी, जो अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। राजस्व के अन्य स्थायी और स्वास्थ्यकर स्रोत खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

यह कहना सही होगा कि राजस्व एक महत्वपूर्ण कामक है जो सरकार के फैसलों को प्रभावित करता है। इन उत्पादों पर लगाए गए टैक्स सरकार के लिए आय का एक बड़ा स्रोत होते हैं, जिसका इस्तेमाल विभिन्न विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं में किया जाता है। अगर सरकार अचानक से इनका उत्पादन बंद कर दे, तो उसे एक बड़े राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिससे अन्य जरूरी सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, यह कहना कि सरकार को सिर्फ राजस्व का ध्यान रहता है और स्वास्थ्य की परवाह नहीं है, पूरी तरह

बॉर्डर इलाकों में बीएसएफ लोगों को दे रही है ड्रोन की ट्रेनिंग

ग्रामीणों को ड्रोन के बारे में जानकारी देने के साथ ही एक ड्रोन को उड़ाकर भी बताया

बीकानेर, (निर्सं)। पाकिस्तान की ओर से बार-बार ड्रोन अटैक होने के बाद बॉर्डर के गांवों में लोगों को ड्रोन के बारे में जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह की आवाज आती है और इस ड्रोन से किस तरह की हरकत हो सकती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों ने बीकानेर बॉर्डर से सटे गांवों में ड्रोन एक्टिविटी के प्रति जागरूक किया।

बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट (इंटेलिजेंस) महेश चंद्र जाट ने बताया कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिससे चराकरा पाकिस्तान बॉर्डर के गांवों में लगातार ड्रोन एक्टिविटी बढ़ा रहा है। बीकानेर ने गांवों ड्रोन के बारे में ग्रामीणों को सामान्य ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह इसका पता चल सकता है। अगर कोई ड्रोन उनके क्षेत्र में घूम रहा है तो

ग्रामीणों को क्या एक्शन लेना है।

डिप्टी कमांडेंट (इंटेलिजेंस) ने बताया कि आने वाले समय में हमारे पड़ोसी देश से ड्रोन की गतिविधियां और भी अधिक बढ़ सकती हैं। इससे निपटने के लिए हर समय तैयार रहना पड़ेगा। आम आदमी को पता होना चाहिए कि ड्रोन कैसे काम करता है और इससे दुश्मन देश को क्या फायदा मिल सकता है। युद्ध जैसे हालात के दौरान यदि आपको कहीं

कोई संदिग्ध वस्तु ड्रोन जैसी दिखाई देती है तो तुरंत ही इसकी सूचना बीएसएफ इंटेलिजेंस को देनी है। ड्रोन के माध्यम से सिर्फ हमले नहीं होते बल्कि देश की सूचना भी एकत्र की जाती है। काफी ऊंचाई पर उड़ने वाले ये ड्रोन कई बार वीडियो और फोटोग्राफी करते हैं। इसलिए ड्रोन का पता चलते ही बीएसएफ को बताना होगा। ड्रोन के माध्यम से बीकानेर, श्रीगंगानगर क्षेत्र में मादक पदार्थों की

तस्करी भी होती है। दोनों देशों के तस्कर एक दूसरे से बात करके ड्रोन के माध्यम से अफीम, स्मैक और अन्य मादक पदार्थ ड्रों में भेजते हैं।

ग्रामीणों को ड्रोन के बारे में जानकारी देने के साथ ही एक ड्रोन को उड़ाकर भी बताया गया। ड्रोन किस तरह से आवाज करता है और ऊंचाई पर उड़ रहे ड्रोन का पता कैसे चल सकता है। ग्रामीणों के साथ सरपंच विजय सिंगड़ भी उपस्थित रहे।

बंद किए गए नाल एयरपोर्ट के सभी रूट फिर से खुले

बीकानेर, (निर्सं)। भारत द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई से पहले भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ सिंह, स्व.गोपास मुंडे जैसे कुछ बड़े नेताओं को छोड़ कर अधिकतर नेता जातीय जनगणना का पानी पी-पी कर विरोध करते थे। अब ऐसे अधिकतर नेता समर्थन करने की होड़ में लाग्ए हैं। खैर पुनीत बात है न, बंदरों की तो, मालिक लोग जैसा नाच सिखाएंगे, वैसे नाच लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर कुछ नए प्रश्न भी उभरे हैं। उनके उत्तर क्या होंगे, उनसे ही पता चलेगा कि इस फैसले के पीछे असली मकसद क्या है? क्या यह केवल और केवल वोटर्स को अपनी ओर लुभाने के लिए ही है ? क्या जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, पिछड़े वर्गों के लोगों की समाजिक, शैक्षणिक व मालिहालत सुधारने के लिए कुछ ठोस निर्णय, योजनाएं बनेंगी और लागू होंगी?

जनगणना अप्रैल 2026 से प्रारम्भ होगी। उस से पहले होगा बिहार विधान सभा के चुनाव। एक परिदृश्य की कल्पना करो कि बिहार में भाजपा को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिलता। भाजपा के वोट बैंक में उसके पारम्परिक वोट बैंक के अतिरिक्त OBC व OBC में बहुत पिछड़े वर्ग के वोट बड़ी संख्या में नही जुड़ते है तो भी, क्या जातियों की गणना कराएंगी, केंद्र सरकार?

एक अन्य बड़ा प्रश्न है, जातियों की गणना करने से सम्बंधित प्रश्न कैसा होगा, क्या-क्या सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी? अभी तो किसी कोने से आवाज निकल रही है, सुझाव आ रहा है कि कोई अलग प्रश्न की आवश्यकता नहीं। वर्तमान प्रश्न पर्याप्त है, उसी में एक कालम जाती का भी हो जाएगा या SC/ST वाले कलम में /OBC और जोड़ दिया जाए लेकिन ऐसा किया जाएगा तो फिर इस गणना का संख्या जानने के अतिरिक्त कोई उपयोगिता नहीं रहेगी।

जाति जनगणना के साथ साथ सम्बंधित व्यक्तियों की शैक्षणिक, वित्तीय स्थितियों यथा घर, वाहन, नौकरी, व्यापार या स्वरोजगार या निर्यामित नौकरी या दिहाड़ी वर्कर, औसत मासिक रोजगार के दिन, वेतन या आमदनी, बैंक से लेनदेन, साहूकार या बैंक से कर्ज, स्वयम की संचित पूंजी, कृषि या अन्य इसी प्रकार की भूमि की जानकारीया एकत्रित करने से ही इस बड़ी एक्ससाइज का कोई उपयोग हो सकेगा। इस प्रकार की जानकारीयों के अध्ययन, विश्लेषण के उपरांत ही सम्बंधित वर्गों के लिए क्या जातियों के अंदर उपजातियों की गणना की जाएगी और अगर ऐसा किया जाएगा तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या होगा?? समाजों को जातियों के बजाय उपजातियों में और विभाजित कर उनकी राजनीतिक हैसियत, उपयोगिता को कम से कमतर करने के लिए?? यह भी ध्यान रखना होगा कि उपजातियां तथाकथित सवर्ण जातियों में भी हैं।

एक ओर बड़ा प्रश्न है—क्या धार्मिक समूहों यथा मुसलमान, ईसाई, सिख आदि में भी जाती-उपजाती पृष्टी जाएगी? इस्लाम, ईसाई आदि में तो सैद्धांतिक आधार पर तो जाती प्रथा मानी नहीं जाती, तो फिर इसका उपयोग क्या होगा? क्या इससे इन धर्मों में पिछड़ों, अति पिछड़ों की पहचान कर उनके लिए सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में दाखिले आदि में इन आंकड़ों का उपयोग होगा? क्या यह संविधान सम्मत होगा या फिर इनके लिए संविधान में संसोधन होगा, जिसका वर्तमान सरकार वाला दल पुर्जोर विरोध करता है??

एक ओर बड़ा प्रश्न है कि क्या जाती जनगणना के पश्चात, इसके आंकड़ों के आधार पर, OBC वर्ग के लिये सरकारी नौकरियों की उपलब्धता में कोई परिवर्तन किया जाएगा? क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाई गई आरक्षण की 50% की सीमा को बदल कर पिछड़ों की जनसँख्यानुसार नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों दाखिलों की वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का साहस सरकार करेगी?? वैसे 50% आरक्षण सीमा सार रूप से, EWS के लिए 10% आरक्षण के बाद समाप्त सी ही तो है। हाँ, EWS आरक्षण के बाद सवर्ण वर्ग के लिए स्वतः 60% का आरक्षण हो गया क्योंकि वर्ग में शामिल नहीं है।

क्या जातियों की जनगणना से सम्बंधित प्रश्न सार्वजनिक होगा? क्या इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा होगी?? और अंत में क्या सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार में जाती/वर्ग आधारित आरक्षण लागू करेगी, जैसी कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों की मांग है???

—अतिथि सम्पादक,

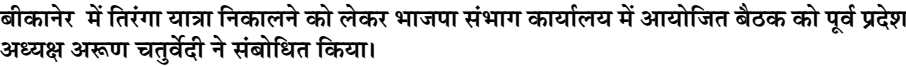
महावीर सिंह,

आई.ए.एस. (से.नि.)

निकलेगी तिरंगा यात्रा

कैंसर हॉस्पिटल के विद्युत पैनल में आग लगने से मची अफरा-तफरी

स्कूल के पास नशा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई



चांबविरया, देवोलात मेघवाल, प्रवक्तृ
अशोक प्रजापत, संयोजक वेदव्यास
विशेष प्रजापत, सह संयोजक राजाराम
सींगड, जसराज सिंवर, प्रधान कानाराम
सींगड, उप प्रधान कन्हैयालाल गेवरा
सारसवत, कलिल शर्मा, धर्मपाल डूडी
मुकुंश सीनी, विशाल गोलडा, दिनेश
चौहान, मेघवाल, प्रेम गहलोत
चंद्रमोहन जोशी, सोहन चहलोत
सर्वेसोदर भोपायिया, भंरलाल जागिड
जगदीश, गुंनराल सीना, जेटमलतल
नाहटा, राधेश्री कडवाल, मीना आसोपा
आसोपा चौधडा, सुशील आचार्य
सरिता नाहटा, रमजात अब्बासी, अजय
खन्नी, राधा खन्नी, अनुराधा आचार्य

बच्ची से दुष्कर्म व हत्या, पहले मिलेगी 2.50 की सहायता

दो नाबालिग के अपहरण के मामले दर्ज

स्टेशन पर मिले बालक को पुलिस ने यूपी छोड़ा

बालक ने अब जाकर यूपी के सहारनपुर शहर की एक मस्जिद को पहचान लिया। इस पर मस्जिद की डिटेल से बालक के शहर की पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम से संपर्क किया गया। उसके परिजनों का पता लगाने को स्टेक होल्डर से भी मदद ली गई।

के अपहरण
ले दर्ज

वहीं पुरानी आबादी घुलसने से रात के समय घर में घुसकर मारपीट और रूपरूप छीनने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी राहुल निवासी पुरानी आबादी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। सीओ (एससी/एसटी सैल) विष्णु खत्री ने बताया कि काफी समय से आरोपी की तलाश की जा रही थी।

रक्तदान शिविर 16 को

बीकानेर, (कास)। जमीन उतलगा-ए-हिन्द शाखा बीकानेर द्वारा 16 मई को सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे तक पीवीएफ अस्पतालता रक्तदान शिविर का आयोजन करेगा जयेगा। रक्त शिविर का उद्देश्य पीवीएफ अस्पतालता में रक्त की भारी कमी को दूर करना है ताकि मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सके। जमीन उतलगा-ए-हिन्द शाखा बीकानेर के महासिचव मौलाना मोहम्मद इरशाद कासमी का कहना है कि रक्तदान से न केवल किसी की जान बचाया जा सकती है, बल्कि यह एक नये कार्य भी है, जो समाज में एकता और सकारात्मक की भावना को बढ़ावा देता है।

[illegible][illegible]

ई- निविदा-रज्जुना सार्व 20/2025/2026
 नगर निगम रज्जुना की ओर से विभिन्न कार्य (कुल 01 कार्य) को जिरवे केंद्र व राज्जा हार्क के अभियांत्रिकी विभागों में "ऐरे", "ऐरे" श्रेणी में पंजीकृत संवेदको एवं नगर निगम में पंजी श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं को से निर्माण प्रयत्न में ई-गोप्रयुक्त प्रक्रिया से ऑन लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साइट www.bikanernmce.org पर वेब साई www.SPPP.raj.nic.in से व leproc@rajasthan.gov.in पर देखी जा सकता है।
 दा की कुल लागत 40.00 लाख
N Number :- DLB2256WSOB04541
 संवाद / सी / 25 / 2300
 आयुक्त
 नगर निगम, बीकानेर

राजस्थान आवासन मण्डल
RAN HOUSING BOARD
 (मंडल अधिनियम १९७० के तहत गठित राज्य सरकार का उपक्रम)
State Government Enterprise
Instituted Under RHB Act 1970)
 वृत्त-बीकानेर, **Circle-Bikaner**

आम सूचना
तएवम धूडारामपुर भोला राम जाति रेगार ने शिवबाडी आवासीय योजना बीकानेर में आवासीय भूखण्डों
में श्रीलाल एवम धूडारामपुर भोला राम जाति रेगार ने उक्त आवासीय योजना में आवंटित भूखण्डों हेतु
57131495 को अपना पंजीकृत मुख्यार आम नियुक्त किया है मुख्यार नामा के आधार पर निम्नानुसार

पूखण्ड संख्या/क्षेत्र फल	चांद संख्या	मुख्यग्रन्थनाम आम/पंजीकृत दिनांक	मुख्यग्रन्थम से क्रेता का नाम/पंजीकृत दिनांक
1-सौ-28/ 210थ.मी.	7(210)/9/81	श्री आशीष चौधरी पुत्र नाथुराम चौधरी 02.05.2024	श्रीमती वीणा व्यास पत्नि श्री विजय शंकर/14.05.2024
1-सौ-29/ 210थ.मी.	7(210)/9/81	श्री आशीष चौधरी पुत्र नाथुराम चौधरी 02.05.2024	श्रीमती वीणा व्यास पत्नि श्री विजय शंकर/14.05.2024
1-सौ-30/ 210थ.मी.	7(210)/9/81	श्री आशीष चौधरी पुत्र नाथुराम चौधरी 02.05.2024	श्रीमती गीता नातु एवम् राहुल नातु /14.05.2024
1-सौ-31/ 210थ.मी.	7(210)/9/81	श्री आशीष चौधरी पुत्र नाथुराम चौधरी 02.05.2024	श्रीमती गीता नातु एवम् श्री राहुल नातु/14.05.2024
1-सौ-32/ 210थ.मी.	7(210)/9/81	श्री आशीष चौधरी पुत्र नाथुराम चौधरी 02.05.2024	श्रीमती गीता नातु एवम् श्री राहुल नातु 14.05.2024

श्री राहु पत्नी श्री राहुल नातु एवम् राहुल नातु पुत्री श्री रघुनाथ नातु न समस्त पंजीयन प्रपञ्चों का सत्वापत्ति त्रिकादिक में अपना नाम नाम करने हेतु आवेदन किया है। श्रीमति घोषा व्यास पत्नी श्री विजय शंकर व्यास, श्री रघुनाथ नातु का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज करने की कायावधि विधाराधीन है। यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों में 10 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल त्रिकादिक यौग्या व्यास पत्नी श्री विजय शंकर व्यास, श्रीमति गीता नातु श्री राहुल नातु एवम् राहुल नातु पुत्र आपराग्य।

+

 $\oplus$  $\oplus$  $\oplus$ 

अजमेर में तीन मंजिला इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी

आग से शोरूम का सामान जलकर राख हुआ, लाखों का नुकसान हुआ

अजमेर, (कांस)। अजमेर शहर में बुधवार सुबह आशागंज रोड स्थित संत कंवरराम स्कूल के पास स्थित तीन मंजिला बिल्डिंग के इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग धीरे-धीरे तीन मंजिला बिल्डिंग में फैल गई। आग से शोरूम में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि बिल्डिंग में दरार आ गई, जिसके चलते आस-पास की अन्य बिल्डिंग को भी खाली करवा लिया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए। दमकल विभाग की चार से अधिक गाड़ियों ने तीन घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

आशागंज रोड स्थित संत कंवरराम स्कूल के पास बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खालसा इलेक्ट्रॉनिक के तीन मंजिला शोरूम में करीब 8:30 बजे शोरूम में अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले



इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी आग को दमकल कर्मियों ने बुझाया।

लिया और कुछ ही देर में पूरी बिल्डिंग को अपने चपेट में ले लिया। शोरूम में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान क्लर, एसी, पंखे पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग के कारण बिल्डिंग को दीवारों व पट्टियों में दरारें आ गईं, जिसके बाद आसपास की अन्य इमारतों और दुकानों

को खाली करवाया गया। आग की सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस, क्लॉक टावर थाना प्रभारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) गजेन्द्र सिंह, पुलिस उपअधीक्षक ओमप्रकाश सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत कार्य के लिए सिविल

डिफेंस, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी को भी बुलाया गया। ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया और आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर विधायक अनिता भदेल भी पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।

■ आग इतनी तेज थी कि बिल्डिंग में दरारें आ गईं, आसपास की अन्य बिल्डिंग को भी खाली करवा लिया गया

शराब के लिए बदमाशों ने एक ही बस में दो बार लूटपाट की

घटना को लेकर वीडियो भी सामने आया है, पुलिस जांच कर रही है

डूंगरपुर, (निर्स)। उदयपुर जिले के पाटिया और फिर डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक ही बस से दो बार लूटपाट हुई। पहले पाटिया में 3 बदमाशों ने 24 हजार 500 रुपए लूट लिए। 12 घंटे बाद 15 साथियों को लेकर बदमाश फिर आए और मोदर के पास बस पर हमला कर दिया। लड़-पत्थरों से बस से जांच फोड़ दिए। सवारियों से मारपीट कर लूटपाट की। हमले में 1 महिला घमटन 3 सवारियों को चोटें भी आईं। घटना को लेकर वीडियो भी सामने आया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।

मनीषा ट्रेवल के संचालक विजय पुत्र ईश्वर गरसिया निवासी खेड़ाघाटी फला गमेती की ओर से पहले पाटिया थाने

- पहले पाटिया में तीन बदमाशों ने बस में 24500 रुपए लूट लिए
- 12 घंटे बाद 15 साथियों को लेकर बदमाश फिर आए और मोदर के पास बस पर फिर हमला कर दिया
- सवारियों से मारपीट कर लूटपाट की, हमले में एक महिला समेत तीन सवारियों को चोटें आईं

और फिर बिछीवाड़ा थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 12 मई को सवारियां लेकर वह बेणेश्वर धाम गया था। सवारियों उतारने के बाद वह वापस बस लेकर जा रहा था। पाटिया थाना क्षेत्र में गंगानगर के पास जाते ही दो बाइक पर तीन बदमाश आए। बदमाशों ने बस को रुकवाकर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। मना करने पर

बदमाशों ने बस का फाटक खोलकर मारपीट की और जेब से 24 हजार 500 रुपए लूट लिए। हो हल्ला होने पर बदमाश बाइक छोड़कर ही भाग गए। बाद में पाटिया थाना पुलिस को दोनों बाइक सौंप दी। पाटिया थाना पुलिस को रिपोर्ट दी गई। संचालक विजय ने बताया कि इसके बाद दूसरे दिन 13 मई को बस

में सवारियों को लेकर देव सोमनाथ की ओर ले जा रहा था। मोदर गांव के पास जाते ही रोड पर 15 बदमाश हाथों में लड़, पत्थर लेकर खड़े थे। बदमाशों ने बस को रोककर हमला कर दिया। बस के सभी कांच फोड़ दिए। बदमाश रूट पर चलने के लिए हफ्ता देने की मांग करने लगे। हफ्ता देने से मना करने पर बदमाश बस में चढ़ गए। बस में बैठी करीब 30 सवारियों को लड़, पत्थरों से बदमाशों ने डराया धमकाया और उनसे भी लूटपाट की। बदमाश सवारियों से भी कैश और अन्य चीजें लूट लीं, लेकिन लोगों से कितनी लूट हुई, इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है। वहीं, मारपीट की वजह से एक महिला सहित तीन सवारियों को गंभीर चोटें आईं है।

सीकर पुलिस 148 बांग्लादेशियों को लेकर जोधपुर पहुंची, डिपोर्ट किया

अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी यहां अपनी शरणस्थली समझकर अवैध रूप से टिके हुए थे

जोधपुर, (कांस)। भारत में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों विशेषकर पाक और बांग्लादेशियों को अब डिपोर्ट किया जाने लगा है। जोधपुर से बुधवार को 148 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी यहां अपनी शरणस्थली समझकर अवैध रूप से टिके हुए थे। अब भारत एक्शन मूड में है। भारत इन अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से बाहर निकलने का क्रम शुरू कर चुका

है और पहली खेप जोधपुर से रवाना कर दी गई है। जोधपुर से 148 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू हुई है। इन बांग्लादेशियों को पहले जोधपुर से पश्चिम बंगाल ले जाया जाएगा और उसके बाद पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग भारत को अपनी शरणस्थली मान बैठे हैं। जब चाहे

भारत में आकर अवैध रूप से रहने लग जाते हैं और भारत में अपने दस्तावेज भी बना लेते हैं। उनके खिलाफ पिछले कुछ दिनों से राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और पूरे प्रदेश में 1008 बांग्लादेशी पकड़े गए। जिला जयपुर रेंज में 761 बांग्लादेशी पकड़े गए। सीकर में कुल 394 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। दस्तावेजों की जांच के बाद 148 बांग्लादेशी नागरिकों को पहली

खेप लेकर सीकर पुलिस जोधपुर पहुंची और यहां से एयर फोर्स स्टेशन से इन्हें पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया। इन सभी लोगों को पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। इन सभी बांग्लादेशों को लेकर सीकर पुलिस आज जोधपुर पहुंची, जहां इन्हें एयर फोर्स स्टेशन के अंदर ले जाया गया और फिर यहां से इन्हें पश्चिम बंगाल भेजने की कार्रवाई शुरू हुई।

स्कूल से पोषाहार चोरी के मामले में दो गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निर्स)। डूंगरपुर के आकाशवाणी केंद्र के पीछे स्थित राजकीय संस्कृत स्कूल, नवाडेरा में हुई पोषाहार चोरी के मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रिंसिपल भारती धील की



सरकारी स्कूल से पोषाहार चोरी के दो और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

है। इनके पास से चोरी के दो गैससिलेंडर बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में राहुल नवाडेरा का रहने वाला है, जबकि अनिल पटेल उदयपुरा का

निवासी है। पहले गिरफ्तार किया गया अमित रोट डोलवरिया ओडा का रहने वाला है, जो अपने मामा के यहां नवाडेरा में रह रहा था।

हाईकोर्ट व लोअर कोर्ट का समय आज से बदलेगा

जोधपुर, (कांस)। राजस्थान हाईकोर्ट व प्रदेश की सभी लोअर कोर्ट का समय ग्रीष्मकाल 15 मई से 27 जून तक की अवधि के लिए बदल जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट (प्रशासन) शैलेंद्र व्यास ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की है।

ग्रीष्मकाल अवधि के दौरान हाईकोर्ट का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इस बीच लंच टाइम 10:30 से 11 बजे तक रहेगा। वहीं कार्यालय समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा और इनके लिए लंच टाइम 10:30 से 10:45 बजे तक रहेगा।

इसी तरह अधीनस्थ न्यायालय का समय भी सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय के ऑफिस का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। कोर्ट और इनके ऑफिस में लंच टाइम सुबह 10 से 10:15 बजे तक रहेगा। इन कोर्ट के पीठासीन अधिकारी सुबह 7:30 से 8 बजे और दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक अपने चैम्बर में कार्य करेंगे।

फरार वांछित आरोपी गिरफ्तार

टोंक, (निर्स)। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में 15 माह से फरार जिला स्तरीय पांच हजार रूपये के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के द्वारा वांछित अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत वृत्ताधिकारी टोंक राजेश विद्यार्थी व मेहनद्वास थानाधिकारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम ने थाने के प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में 15 माह से फरार व पांच हजार रुपए का इनामी आरोपी रमेश पुत्र लादूराम बैरवा निवासी मोरडा थाना मेहनद्वास हाल निवासी एजेन्सी एरिया देवली जो शांति किस्म का अपराधी था, जो बार बार मोबाइल सिम व अपना नाम पता बदलकर अलग-अलग जगह छुपकर रह रहा था। जिसको

टीम द्वारा अहमदपुरा चौकी से डिटेन कर गिरफ्तार किया गया, जिसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा। इसी क्रम में देवली वृत्ताधिकारी रामसिंह जाट व दुनी थानाधिकारी हेमन्त जनागल के नेतृत्व में गठित टीम ने थाना देवली के स्मैक तस्करी के मामले में दो साल से फरार पांच हजार के इनामी को तकनीकी व मुखबीर की सूचना पर स्मैक तस्करी के मामले में आरोपी बंटी बंजारा पुत्र बहादुर बंजारा निवासी जीवा नायक का खंडा थाना गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ को गत रात्रि को गिरफ्तार किया जाकर जिसे न्यायालय के आदेश पर पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। मुल्जिम ने पिछले दो साल में हैदराबाद व चैन्नई शहरों में कन्बल व कुर्सियां बेचने का काम करते हुए फरारी काटी थी।

छात्रा ने आत्महत्या की

डूंगरपुर, (निर्स)। धम्बोला थाना क्षेत्र के गडापट्टापीठ गांव में एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान असीना के रूप में हुई है। वह दसवीं कक्षा की छात्रा थी। घटना मंगलवार सुबह की है। असीना का शव उसके घर के बाहर एक पेड़ से लटक का मिला। सोमवार शाम को उसका अपने भाई से झगडा हुआ था। असीना ने इस बारे में अपने पिता आशीष कटारा को फोन

पर बताया था। आशीष कटारा और उनकी पत्नी गुजरात में मजदूरी करते हैं। उनके तीन बच्चे घर पर रहते थे। झगड़े की जानकारी मिलने पर पिता ने फोन पर दोनों बच्चों को डांटा था। उन्होंने वापस आकर मामला सुलझाने की बात कही थी। माता-पिता भी गुजरात से तुरंत घर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को पेड़ से उतारा। शव को सीमलवाडा अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया।

JKK Jawahar Kala Kendra, Jaipur			
	NIB JKK2526A0006 UBN: JKK2526GSOB000006	NIB JKK2526A0008 UBN: JKK2526SSOB000008	NIB: JKK2526A0007 UBN: JKK2526SSOB000007
1 उपापन अधिकारी	अतिरिक्त महानिदेशक	अतिरिक्त महानिदेशक	अतिरिक्त महानिदेशक
2 बोली का संक्षिप्त विवरण	जवाहर कला केन्द्र के ग्राफिक स्टूडियो एवं कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी/आर्ट एण्ड क्राफ्ट सामग्री आपूर्ति हेतु दर निविदा अनुबंध	जवाहर कला केन्द्र द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु स्टैण्ड्री/बैनर/फ्लेक्स आदि से प्रिन्टिंग कर विज्ञापन के कार्य की आपूर्ति	जवाहर कला केन्द्र द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु विभिन्न प्रकार के मुद्रण पोस्टर, ब्रोशर, निमंत्रण पत्र, पम्पलेट, टिकट, प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र इत्यादि कार्य के आपूर्ति हेतु
3 बोली की अनुमानित लागत	रुपये 6.00 लाख (मय जी.एस.टी.)	रुपये 9.50 लाख (मय जी.एस.टी.)	रुपये 6.00 लाख (मय जी.एस.टी.)
4 बोली का प्रकार	खुली प्रतियोगी बोली द्वारा दर संविदा	खुली प्रतियोगी बोली द्वारा दर संविदा	खुली प्रतियोगी बोली द्वारा दर संविदा
5 बोली विक्रय (Download) प्रारंभ करने की दिनांक एवं समय	दिनांक 13.05.2025 अपरान्ह 4:00 बजे (Can be downloaded from http://sppp.raj.nic.in & jkk.artandculture.rajasthan.gov.in)	दिनांक 13.05.2025 अपरान्ह 4:30 बजे (Can be downloaded from http://sppp.raj.nic.in & jkk.artandculture.rajasthan.gov.in)	दिनांक 13.05.2025 अपरान्ह 4:30 बजे (Can be downloaded from http://sppp.raj.nic.in & jkk.artandculture.rajasthan.gov.in)
6 बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी	दिनांक 16.05.2025 अपरान्ह 3:00 बजे	दिनांक 19.05.2025 अपरान्ह 3:00 बजे	दिनांक 19.05.2025 अपरान्ह 3:00 बजे
7 बोली प्रपत्र की कीमत	रुपये 500/-, डी.डी./बैंकर्स चेक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।	रुपये 500/-, डी.डी./बैंकर्स चेक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।	रुपये 500/-, डी.डी./बैंकर्स चेक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
8 बोली प्रतिभूति (Bid Security)	लागत राशी का 2 प्रतिशत राशी रुपये 12,000/-, डी.डी./बैंकर्स चेक/एफ.डी. आर. अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।	लागत राशी का 2 प्रतिशत राशी रुपये 19,000/-, डी.डी./बैंकर्स चेक/एफ.डी. आर. अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।	लागत राशी का 2 प्रतिशत राशी रुपये 19,000/-, डी.डी./बैंकर्स चेक/एफ.डी. आर. अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
9 तकनीकी बोली खोलने की दिनांक	दिनांक 16.05.2025 को अपरान्ह 5.00 बजे	दिनांक 20.05.2025 को अपरान्ह 2.00 बजे	दिनांक 20.05.2025 को अपरान्ह 2.00 बजे
10 वित्तीय बोली खोलने की दिनांक व समय	तकनीकी बोली में सफल बोली दाताओं को सूचित किया जायेगा	तकनीकी बोली में सफल बोली दाताओं को सूचित किया जायेगा	तकनीकी बोली में सफल बोली दाताओं को सूचित किया जायेगा
11 बोली जमा कराने/खोलने का स्थान	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर - 302004	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर - 302004	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर - 302004
12 बोली की वैधता अवधि	बोली जमा कराने की तिथि से 90 दिवस	बोली जमा कराने की तिथि से 90 दिवस	बोली जमा कराने की तिथि से 90 दिवस
13 आपूर्ति अवधि	आपूर्ति आदेश दिये जाने पर ग्राफिक स्टूडियो एवं कार्यालय उपयोग हेतु स्टेशनरी/आर्ट एण्ड क्राफ्ट सामग्री स्टोर अनुभाग को निर्दिष्ट अवधि में आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।	आपूर्ति आदेश दिये जाने बैनर/फ्लेक्स प्रिन्टिंग से संबंधित कार्य कार्यक्रम तिथि से 2 दिवस पहले अथवा निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।	आपूर्ति आदेश दिये जाने पर विभिन्न प्रकार के मुद्रण पोस्टर, ब्रोशर, निमंत्रण पत्र, पम्पलेट, टिकट, प्रमाण-पत्र, पहचान-पत्र इत्यादि से संबंधित कार्य कार्यक्रम तिथि से 2 दिवस पहले अथवा निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।
14 बोली हेतु अधिकृत अधिकारी	अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर	अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर
- बोली दाता, बोली दस्तावेज में उल्लेखित निर्धारित समयवाधि में जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के स्टोर अनुभाग से बोली शुल्क जमा करवाकर बोली प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं, या स्वयं जवाहर कला केन्द्र की वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में बोली शुल्क जरुरि डिमाण्ड ड्राफ्ट (अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर) जमा कराना होगा। बोली शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोली दाता को तकनीकी रूप से असफल माना जायेगा व उनकी वित्तीय बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। - बोली प्रस्ताव पूर्ण रूप से भरा हुआ मय हस्ताक्षर एवं संलग्नों के साथ उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता के कक्ष में रखे सील-बंद बाक्स में निर्धारित समय एवं तिथि पर जमा करावें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त बिड बिना किसी विचार के निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्राप्त होने में हुई देरी के लिये विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।			
रज.सं/हा.एल/सी/25/2310 अतिरिक्त महानिदेशक जवाहर कला केन्द्र, जयपुर			

नेपाली गैंग ने की चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर कांग्रेस नेता के घर लूटपाट

नौकर दम्पति सहित दो साथियों ने दी वारदात को अंजाम

जयपुर। वैशाली नगर थाना इलाके में बुधवार सुबह नेपाली गैंग के नौकर दम्पति सहित उनके दो साथियों ने कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जानकारी में सामने आया कि गैंग ने नेता की मां और पत्नी को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर सोने-चांदी के जेवरारत सहित नकदी लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी लेकर इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन नेपाली गैंग के सदस्यों को कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज सहित खंगालने में जुटी है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम

- सास-बहू मेट्रो मास हॉस्पिटल में भर्ती
- कांग्रेस नेता संदीप चौधरी रहे चुके हैं भूमि विकास बोर्ड के अध्यक्ष
- पुलिस ने की इलाके में नाकाबंदी, फिलहाल नहीं लगा कोई सुराग

अमित कुमार ने बताया कि वैशाली नगर थाना इलाके के आनंद नगर इलाके के रहने वाले भूमि विकास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर लूट की वारदात हुई है। जहां मुख्य आरोपी नेपाली नौकर काजल और भरत ने उनकी मां कृष्णा (75) और उनकी पत्नी ममता (43) को चाय में नशीला

पदार्थ पिला दी। बेहोश होने के बाद आरोपियों ने दो अन्य साथियों को बुलाकर लूटपाट कर फरार हो गए। पुलिस जानकारी में सामने आया कि कांग्रेस नेता संदीप ने बुधवार सुबह साढ़े सात बजे पहले मां और फिर पत्नी को फोन किया। लेकिन दोनों ने नहीं उठाया। इसके बाद बेटी राजश्री को फोन किया।

राजश्री ने कमरे से निकलकर देखा तो दादी और मां दोनों कमरे में बेहोश थी। कांग्रेस नेता फिर पड़ोस में रहने वाले भांजे रोहित को कॉल किया। रोहित ने अपने पिता को भेजा। जहां दोनों महिला बेहोशी हालत में मिलने पर मेट्रो मास हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना के वक्त संदीप चौधरी का 13 साल का बेटा राजदीप भी घर पर ही था। बताया जा रहा कि कांग्रेस नेता के परिवार ने नेपाल के रहने वाले पति-पत्नी को 10 दिन पहले ही खाना बनाने के काम पर रखा था। फिलहाल मुख्य आरोपी नौकर पति-पत्नी के साथ उनके दो साथियों की तलाश की जा रही है। जयपुर शहर में नाकाबंदी भी कराई गई है।

बस सारथियों को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी में सालों से संविदा पर कार्यरत बस सारथियों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरएसआरटीसी के एमडी और कार्यकारी निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सुभाष चन्द व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता सुरेंद्र लॉबा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता

2346 फार्मासिस्ट का पदस्थापन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवरसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रिकत पदों पर भर्ती एवं पदस्थापन के कार्य को पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूरा कर रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 2346 फार्मासिस्ट की नियुक्ति करते हुए उन्हें प्रदेशभर में विभिन्न रिकत पदों पर पदस्थापित किया है।

बीकानेर तकनीकी विवि.में कुलगुरु नियुक्त

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आदेश जारी कर प्रो.अखिल रंजन गर्ग को बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। बागडे ने कुलगुरु पद पर यह नियुक्ति प्रो. अखिल रंजन गर्ग के कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले के लिए की है।

मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की सफल क्रियान्विति के निर्देश



सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बुधवार को नेहरू सहकार भवन स्थित राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उनको स्वागत किया गया।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बुधवार को नेहरू सहकार भवन स्थित राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान बैंक अधिकारियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना की प्रगति जानकारी प्राप्त की।

दक ने योजना को समुचित रूप से क्रियान्वित करते हुए अधिक से अधिक

पात्र ऋणी सदस्यों को योजना से लाभान्वित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से योजना के संबंध में की जा रही कार्यवाही और अब तक की प्रगति की जानकारी ली। एसएलडीबी के प्रबंध

निदेशक श्री जितेन्द्र प्रसाद ने अवगत कराया कि योजना के तहत 13 मई तक 21 हजार 812 पात्र ऋणियों को नोटिस तामील करवाये जा चुके हैं तथा कुल 921 मामलों में 21.96 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के स्तर पर वसूली में सहयोग एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए एसएलडीबी से प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

इस दौरान सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन प्राथमिक बैंकों में प्रगति आशानुरूप नहीं है, वहां अधिक फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष में पहली बार राज्य सरकार भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए

यह महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है, जिससे भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और ऋणी सदस्यों को मुख्यधारा में आने व पुनः निवेश ऋण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अतः अधिकारी पूरे मनोयोग से प्रयास करते हुए योजना की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने बैंक परिसर में विराजमान भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश के किसानों की खुशहाली और दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के पुनरूद्धार की कामना की। एसएलडीबी की महाप्रबंधक उषा कपूर सहित अन्य बैंक अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

व्हाट्सअप बॉट के जरिये एलआईसी प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे

जयपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने आज व्हाट्सअप बॉट के माध्यम से प्रीमियम भुगतान के लिये ऑनलाइन सुविधा का आनावरण किया।

इस फीचर का शुभारंभ 9 मई को सीईओ और एमडी सिद्धार्थ महान्ति के द्वारा सभी प्रबंध निदेशकों एम.जगन्नाथ, तवलेश पोंडे, सतपाल भातु और आर. दुरैस्वामी और निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। यह विकल्प एलआईसी ग्राहकों को प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन करने का एक और वैकल्पिक विकल्प प्रदान करेगा। पंजीकृत ग्राहक पोर्टल उपयोगकर्ता भुगतान के लिये देय पॉलिसियों का पता लगाने के लिये व्हाट्सअप नंबर का उपयोग कर सकते हैं। और सीधे व्हाट्सअप बॉट के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। ग्राहक के प्रीमियम के लिये देय पॉलिसियों की पहचान करने से लेकर भुगतान और रसीद बनाने तक का कार्य किया जायेगा। सीईओ महान्ति ने कहा कि यह विकल्प एलआईसी के ग्राहकों के लिये संचालन के कार्य को आसान बनाएगा और तेजी से बढ़ रहे व्हाट्सअप के माध्यम से कहीं से भी कहीं एलआईसी प्रीमियम का भुगतान करने के लिये एक आसान उपकरण होगा।

छह साल से कोचिंग सेंटर्स के लिए न कानून बना ना गाइडलाइन लागू हुई : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों की ओर से आत्महत्या करने से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यह बड़े दुख की बात है कि साल 2019 से इस संबंध में कानून बनाने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने का कानून नहीं बना है। इसके अलावा कानून बनने तक बनाई गई गाइडलाइन को भी लागू नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस मुकेश राजपुरोहित ने यह आदेश मामले में लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई

करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि आत्महत्याओं को लेकर न्यायमित्र की ओर से पूर्व में पेश आंकड़ों का सत्यापन किया गया है। इस साल जनवरी माह से 8 मई तक 14 विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है। दूसरी ओर एक कोचिंग सेंटर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जिस पर 23 मई को सुनवाई होनी है। ऐसे में तब तक हाईकोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं दिया जाए। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद रखी है।

जन सेवा का उदाहरण बनी मुख्यमंत्री की जन-सुनवाई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील, सेवाभावी और सर्वस्पर्शी कार्या की त्रिवेणी ने आमजन की परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण करने का एक तंत्र सुविकसित किया है। जन सेवा को सर्वाच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता के साथ परिवेदनाओं को उसके निष्कर्ष तक पहुंचाना इस तंत्र का आधार है। इससे प्रदेश के युवा, महिला, मजदूर और किसान सहित सभी वर्गों को सुगम सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री शर्मा के सुस्पष्ट निर्देशों की अनुपालना में जनता की समस्याओं का समयबद्धता निस्तारण किया जा रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई ने जनसेवा का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है।

‘महिला उद्यमी ऋण योजना’ के तहत सस्ती ब्याज दरों पर मिलेगा ऋण

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सदस्यों को लखपति दीदी बनाने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस मुहिम में अब रास्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉन्फेड) भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के साथ ही राज्य सरकार का बजट घोषणा के अनुरूप श्री अन्न उत्पादों को कॉन्फेड एवं सहकारी उपभोक्ता षंडारों के उपहार केन्द्रों पर विक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कॉन्फेड के माध्यम से राजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय में वृद्धि की संभावनाओं तलाशने के निर्देश दिए गए थे। इस क्रम में यह अभिनव पहल की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में कॉन्फेड एवं 33 जिला उपभोक्ता सहकारी षण्डारों के 78 उपहार विक्रेता केन्द्रों पर राजीविका महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के साथ ही श्री अन्न उत्पाद विक्री के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

राजपाल ने बताया कि जयपुर के भवानी सिंह रोड स्थित कॉन्फेड के नवजीवन संघ एवं अन्य एवं एक कंटेनर विशेष रूप से राजीविका के उत्पादों की विक्री एवं डिस्प्ले के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

सहकार मसाला मेले में श्री अन्न से बने उत्पाद बने आकर्षण का केन्द्र

जयपुर। सहकारिता विभाग एवं राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ द्वारा जवाहर कला केन्द्र में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले में इस बार श्री अन्न से बने उत्पाद खास आकर्षण का केन्द्र बने हैं। जयपुरवासियों को ये उत्पाद खास पसंद आ रहे हैं और

■ मेले में जमकर हो रही श्री अन्न से बने उत्पादों की खरीददारी

वे उत्साह के साथ इनकी खरीददारी कर रहे हैं।

मेले में कॉन्फेड की स्टॉल के साथ ही लगभग 25 स्टॉल्स पर श्री अन्न से बने उत्पाद उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होने के कारण इन प्रोडक्ट्स की विशेष रूप से डिमांड देखने को मिल रही है। मेले में कॉन्फेड की स्टॉल पर सुश्री अम्बिका ने बताया कि उनके यहां मिलेट मिक्स, रोस्टेड ज्वार, रोस्टेड बाजरा, रागी के बिस्किट, ओट्स बिस्किट, ज्वार की नान खटाई आदि उत्पाद उपलब्ध हैं, जो ग्राहकों द्वारा खूब पसंद किए जा रहे हैं। वहीं, के.डी. स्वयं सहायता समूह, राजीविका-करोली की स्टॉल पर आदिशर्मा ने बताया कि उनकी स्टॉल पर श्री अन्न से बने 11 वैरायटी के कुकीज उपलब्ध हैं, जो उनकी माता द्वारा घर पर ही तैयार किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि स्टॉल पर आने वाले ज्यादातर लोगों को ये बहुत पसंद आ रहे हैं और इनकी अच्छी विक्री हो रही है।



सहकार मसाला मेले में कॉन्फेड की स्टॉल के साथ ही लगभग 25 स्टॉल्स पर श्री अन्न से बने उत्पाद उपलब्ध हैं।

इसी प्रकार, नन्या स्वयं सहायता समूह, जयपुर की स्टॉल पर मिलेट कुकीज के साथ ही श्री अन्न के पास्ता, नूडल्स, पोहा और सूजी भी उपलब्ध हैं। स्टॉल पर मौजूद मनीष जैन ने बताया कि 5 प्रकार के श्री अन्न सावां, कुटकी, कोदो, कांगनी और छोटी कांगनी भी उनके यहां उपलब्ध है। स्वास्थ्य को लेकर जागरूक लोग इन प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं और जमकर खरीददारी भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्री अन्न और श्री अन्न से बने ये उत्पाद मधुमेह, कैंसर, थायराइड, मोटापा, आर्थराइटिस,

एनीमिया, हृदय रोग, वात रोग आदि के उपचार में सहायक होते हैं। कोटा जिला सहकारी उपभोक्ता सहकारी संघ की स्टॉल पर पीयूष शर्मा ने बताया कि उनके यहां मखाना मिक्स फलाहारी दलिया, मल्टीग्रेन दलिया, रागी के फ्लेक्स, सावां के रोस्टेड फ्लेक्स, श्री अन्न का दलिया, शुगर फ्री गेहूं रहित आटा आदि उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को अब श्री अन्न का महत्व समझ में आ रहा है और जो भी ग्राहक ये प्रोडक्ट्स खरीदकर ले जा रहे हैं वे इन्हें खरीदने के लिए वापस भी आ रहे हैं।

मेले में खरीददारी के लिए पहुंच रहे लोग भी इन श्री अन्न उत्पादों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जयपुर के सिद्धार्थ नगर की निवासी विमला मौणा ने बताया कि उनके पति चिकित्सक हैं और परिवार में सब स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं, इसलिए श्री अन्न से बने उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि मेले में कम दामों में शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल रहे हैं। गांधी नगर निवासी अनिता ने कहा कि खान-पान में बदलाव के कारण लोगों में कई प्रकार की बीमारियां घर कर रही हैं।



जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बुधवार को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट, सराहनीय, मेहनत, लगन एवं समर्पण से कार्य करने वाले छह पुलिसकर्मियों को “कांस्टेबल ऑफ दी मंथ” के अवार्ड से सम्मानित किया।

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बुधवार को जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट, सराहनीय, मेहनत, लगन एवं समर्पण से कार्य करने वाले छह पुलिसकर्मियों को “कांस्टेबल ऑफ दी मंथ” के अवार्ड से सम्मानित किया।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि अप्रैल माह 2025 का “कांस्टेबल ऑफ दी मंथ” पुरस्कार के लिए जिला पूर्व से चिन्हित महिला कांस्टेबल पुलिस थाना बजाजनगर अन्नपूर्णा ने कार्य बड़ी मेहनत लगन एवं रुचि से कुशलतापूर्वक राजकाय सम्पन्न किया है। वहीं जिला पश्चिम के कांस्टेबल पुलिस थाना बगरू हंसराम ने ज्वैलर्स की दुकान में हथियार दिखाकर सोने-

चांदी के गहने लूटने के घटना स्थल एवं आने-जाने के रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग देखकर व आस-पास के लोगों से जानकारी प्राप्त कर वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों को चिन्हित कर आरोपी सोहेल, कन्हैयालाल व प्यारेलाल को दस्तयाब कर लूटे हुये गहने व वारदात में प्रयुक्त हथियार एवं वाहन को बरामद करवाने में अहम भूमिका निभायी। जिला उत्तर के कांस्टेबल पुलिस थाना विद्याधनगर महिलाल ने वाछित ईनामी अपराधी आदित्य कुमावत को चिन्हित कर कड़ी मेहनत व आसुचना संकलित कर गिरफ्तार कराया व अन्य वाहन चोरी की वारंताों का खुलासा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जिला दक्षिण

के पुलिस थाना श्यामनगर के कांस्टेबल पवन कुमार ने शातिर चैन स्नेचर वारिस खान को गिरफ्तार करवाने में एस्कार्ट सर्विस के नाम पर लूटमार करने वाली गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में एक अन्य प्रकरण में चार नकबजन एवं दो खरीददाराों को गिरफ्तार करवाकर 2.5 लाख रूपये का माल बरामद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। यातायात शाखा पूर्व के कांस्टेबल हरीश कुमार ने जयपुर शहर के न्यस्ततम गोविन्द मार्ग पर हांक में तैनात रहते हुये आमजन को सुगम यातायात प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक कार्यवाही करते हुये यातायात को सुगम संचालन में देर रात्री तक ड्यूटी कड़ी मेहनत व लगन से किया है।

करोड़ों रुपये की ठगी का फरार इनामी आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

आरोपी ने लोगों से प्रोपर्टी में निवेश कराकर करोड़ों रूपयों की ठगी की थी

कोटा, (निसं)। लोगों से प्रोपर्टी में निवेश कराकर करोड़ों रूपयों की ठगी करने के मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी को रामपुरा कोतवाली पुलिस टीम ने जयपुर से गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि स्थाई वारंटी, फरारी काट रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर समस्त थानों के थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शहर एसपी ने बताया कि करोड़ों रूपयों की ठगी में फरार 5 हजार रुपये के इनामी स्थाई वारंटी आरोपी इरफान अंसारी ने लोगों को रुपये दुगने करने का सपना दिखाकर करोड़ों रूपयों की ठगी की थी, जिसके विरूद्ध विभिन्न



रामपुरा कोतवाली पुलिस ने ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया।

न्यायालयों में कई प्रकरण लम्बित है। न्यायालयों से 16 वारंट जारी किये आरोपी के खिलाफ विभिन्न

- आरोपी के खिलाफ विभिन्न न्यायालयों से 16 वारंट जारी किये गये थे, परिवार के साथ जयपुर में रह रहा था

अंसारी का रेंज स्तरीय मोस्ट वांटेड टॉप 10 सूची में चयन किया था। शहर एसपी ने बताया कि फरार इनामी आरोपी की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उपअधीक्षक राजेश कुमार टेलर के निर्देशन में रामपुरा कोतवाली थाने के उपनिरीक्षक थानाधिकारी महेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने आरोपी के रिश्तेदारों में उसकी

काफी तलाश की, लेकिन जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी इरफान अंसारी परिवार सहित कई वर्षों से फरार चल रहा है।

शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम को तकनीकी आधार व मुखबीर द्वारा आरोपी के जयपुर में खो-नागोरियन क्षेत्र में छुपे होने की सूचना मिली। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने खोनागोरियन क्षेत्र में आरोपी इरफान अंसारी के छुपने के संभावित ठिकानों पर रैकी कर आरोपी को जे.एन.यू अस्पताल, खोनागोरिया जयपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। शहर एसपी ने बताया कि आरोपी नें लोगों को प्रोपर्टी में निवेश कर रूपये दुगने करने के नाम पर करोड़ों रूपयों की ठगी की थी। पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

होटल से अवैध मादक पदार्थ सहित दो जने गिरफ्तार

सांभरझील, (निसं)। मोखमपुरा पुलिस ने नशा कारोबारियों को गिरफ्तार कर उनके पास 3१2 ग्राम अफीम व 1 किलो 200 ग्राम डोडा-पोस्ट चूरा बरामद किया है।

- अफीम व डोडा-पोस्ट चूरा व छिलका जब्त किया



मोखमपुरा पुलिस ने दो जनों को गिरफ्तार किया।

दो संदिग्ध व्यक्तियों नाराणाराम पुत्र भूराराम जाट निवासी माचरों की ढाणी रामसर का कुआं थाना सिणधरी जिला बाड़मेर व हनुमान राम पुत्र ठाकराराम जाट निवासी देलुआ की ढाणी बनकों का बेरा थाना सदर बाड़मेर जिला बाड़मेर की तलाशी ली तो व्यक्ति हनुमान राम के पास एक प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ अफीम 3१2 ग्राम मिला तथा दूसरे व्यक्ति नाराणाराम की तलाशी ली तो उसके पास से प्लास्टिक की थैली में अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 20 ग्राम डोडा-पोस्ट

चूरा व छिलका मिला। दोनों नशे के कारोबारियों को बिना लाइसेंस व परमिट के मादक पदार्थ की सप्लाई करने पर मौके पर ही गिरफ्तार किया जाकर कब्जे से अफीम व डोडा-पोस्ट चूरा व छिलका को जब्त किया गया तथा दोनों के खिलाफ पुलिस थाना मोखमपुरा पर एनडीपीएस एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी अवैध मादक पदार्थ कहां से लेकर आते हैं तथा किस किसको सप्लाई करते हैं इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है।

गैस सिलेण्डर में आग लगी, किचन जला

कार्यक्रम के दौरान देवरानी-जेठानी खाना बना रही थी, लीकेज से पकड़ी आग

पाली, (नि.सं.)। पाली में बुधवार की सुबह एक घर में सामाजिक प्रोग्राम के चलते किचन में देवरानी-जेठानी काम वाली बाई के साथ मिलकर खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। घबराकर महिलाएं किचन से भागीं। घरवालों ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। हिमन्त दिखाते हुए एक युवक जलता हुआ सिलेंडर मकान के फर्स्ट फ्लोर से लेकर बाहर आया और बुझाया। इस हादसे में पूरा किचन चल गया और कुछ बिस्तर भी जल गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

- एक युवक जलता हुआ सिलेंडर मकान के फर्स्ट फ्लोर से लेकर बाहर आया और बुझाया

एसआई ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि पाली जनता कॉलोनी जाट छात्रावास के सामने की तरफ रहने वाले मनोज पंवार पुत्र लक्ष्मीनारायण पंवार के फूफाजी के देहांत होने पर बुधवार को उनके घर पर सामाजिक प्रोग्राम था।

इसको लेकर उनकी पत्नी संतोष अपनी देवरानी ममता और काम वाली बाई के साथ मेहमाने के लिए खाना बना रहे थे। सुबह के करीब सवा सात बजे अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। घबराकर तीनों किचन से बाहर आ गईं। मनोज पंवार दौड़ के मकान के फर्स्ट फ्लोर पर गया जहां किचन था। बिस्तर गीला कर सिलेंडर पर डाला लेकिन आग स्प्रीड से लग रही थी और सिलेंडर बुझा नहीं। पीड़ित मनोज पंवार ने घटना को लेकर गैस सिलेंडर एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया।



जैसलमेर : जैसलमेर विधायक छोटूरसिंह भाटी ने बुधवार को शहर के रामगढ़ रोड स्थित सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात की। इस अवसर पर बाड़मेर-जैसलमेर पूर्व सांसद कैलाश चौधरी, पोकरण विधायक मंहत प्रतापपुरी महाराज, कंवराजसिंह, भाजपा जैसलमेर अध्यक्ष दलपत हिंण्डा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी तथा उनके अदम्य साहस और देशभक्ति के लिए कृतज्ञता व्यक्त की।

नंबर कम आने पर छात्र ने आत्महत्या की

कोटा, (निसं)। जवाहर नगर थाना इलाके में एक दसवीं कक्षा के छात्र ने घर में फर्श का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जो

बाल विवाह रुकवाया

सलूंबर, (कासं)। जिला प्रशासन सलूंबर एवं गायत्री सेवा संस्थान की संयुक्त पहल से सराडा ब्लॉक के गांव बलुआ में हो रहा एक बाल विवाह समय रहते रोक़ा गया।

गायत्री सेवा संस्थान के जिला समन्वयक पायल कनेरिया तथा फ़ील्ड समन्वयक रमेश चौबीसा को सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग बालक का विवाह होने जा रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासन को सूचित किया गया। तत्पश्चात दिखाते हुए अतिरिक्त विकास अधिकारी कैदार नारायण, सहायक विकास अधिकारी हरीश, ग्राम विकास अधिकारी नरेश कुमार प्रजापत, पटवारी

गोकुलचंद मीणा मौके पर पहुंचे। मौके पर विवाह की पूरी तैयारियां चल रही थीं, टेंट लग चुका था और मेहमान भी पहुंच चुके थे। जब बालक के दस्तावेजों की जांच की गई, तो यह स्पष्ट हुआ कि उसकी आयु मात्र 1१ वर्ष है जबकि कानूनी रूप से विवाह हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा परिवार को समझाईश की गई जिसके पश्चात परिजनों ने विवाह को स्थगित करने पर सहमति जताई और भविष्य में बालिग होने तक विवाह न करने का लिखित रूप में आश्वासन दिया। उसी समय टेंट हटवाए गए और विवाह की अन्य तैयारियां भी रुकवा दी गईं।

एसआई की कार पलटी, एक हाथ टूटा

पाली, (नि.सं.)। पाली में कार पलटने से एसआई का हाथ टूट गया और बांड़ी में कई जगह चोटें आईं। इलाज के लिए मंगलवार देर रात को उन्हें पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनके टूटे हाथ का ऑपरेशन होगा। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी

- घायल एसएसआई का अस्पताल में इलाज जारी, अधिकारी मिलने पहुंचे

पी हॉस्पिटल पहुंचे। पाली जिले के गुड़ा एंदला थाने के खौड़ चौकी में कार्यरत पुखराज मंगलवार रात को गुड़ा एंदला से कीरवा जा रहे थे। इस दौरान कीरवा के निकट उनकी गाड़ी नाले में फंस कर पलट गई। हादसे में उन्हें चोटें आईं और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। मंगलवार रात करीब साढ़े दस बजे उन्हें इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। जहां उनका उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीण रतनाराम देवासी, गुड़ा एंदला कपूराराम सहित कई पुलिसकर्मी बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे और घायल की सेहत की जानकारी ली।

चोरी व नकबजनी मामले में दो आरोपी गिरफ्तार



निवाई थाना क्षेत्र में नकबजनी व चोरी मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया।

टोंक, (निसं)। निवाई थाना क्षेत्र में नकबजनी व चोरी की हुई वारदात के मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया है। मृत्युन्जय मिश्रा, उप-अधीक्षक निवाई व निवाई थाना प्रभारी रामजीलाल द्वारा गठित टीम ने पाइप फैक्टरी में कार्यरत रामलाल से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ व फैक्टरी में लगे सीसीटीवी

फुटेज के साक्ष्य के आधार पर आरोपी रामलाल पुत्र रामबिलास मीणा निवासी रूपवास को डिटेन कर अनुसंधान किया गया तो उसने 5 तारों का बण्डल चुराकर अजय पुत्र लेखराज खटीक निवासी गंगाबिहार कॉलोनी गोनेर थाना शिवदासपुरा जिला जयपुर को कबाड़ी के बेचना स्वीकार किया। अजय को

डिटेन कर पूछताछ के दौरान वारदात में शामिल होना स्वीकार किया। इस दौरान चोरी किये गये तारों के बण्डलों को भी उनके कब्जे से जब्त किया तथा उक्त घटना में प्रयुक्त की मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

दौसा/रामगढ़ पंचवारा, (निसं)। अमराबाद सरकारी स्कूल के शिक्षक धनपाल मीणा पर छात्रा को अगवा करने का आरोप लगा है। परिजनों ने झॉपदा थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई है। घटना के विरोध में बुधवार को ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरना दिया। ग्रामीण आरोपी की गिरफ्तारी और छात्रा की बरामदगी की मांग कर रहे थे। धरना प्रदर्शन करीब पांच घंटे चला। सूचना पर लालसोट के एसपी दिनेश अग्रवाल, एसडीएम बन्नी नारायण मीणा, तहसीलदार मदन लाल मीणा और थाना अधिकारी रामशरण गुर्जर मौके पर पहुंचे। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्कूल पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश कर ताला खुलवाया और प्रदर्शन खत्म करवाया। जानकारी के अनुसार, आरोपी शिक्षक 2014 से अमराबाद स्कूल में पदस्थ है। वह शादीशुदा है। परिजनों ने बताया कि 8 मई को शाम 4 बजे छात्रा



ग्रामीणों ने कारवाई की मांग को लेकर धरना दिया।

अपनी छोटी बहन के साथ स्कूटी से प्रैक्टिकल की फाइल लेने जा रही थी। निज़राने के पास आरोपी ने स्कूटी को टक्कर मारी। फिर जमात चौराहे के पास दोबारा टक्कर मारकर दोनों बहनों को गिरा दिया। इसके बाद 22 साल की बड़ी

बहन को जबरन अपनी गाड़ी में डालकर फरार हो गया। छोटी बहन किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया।

प्रदर्शन में शामिल भामाशाह

प्रहलाद मीणा ने कहा कि ऐसे शिक्षक को शिक्षा विभाग से बर्खास्त किया जाना चाहिए। 8 मई को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस दौरान भामाशाह प्रहलाद मीणा

- परिजनों ने झॉपदा थाने में अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई, छात्रा की बरामदगी की मांग की

- घटना के विरोध में ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर धरना दिया

, सरपंच राकेश हल्कारा, हीरा लाल मीना, घासी लाल मीणा, उमाशंकर मीणा, शोराम पटेल, भरत मीणा, अमरचंद पटेल, सहित आदि मौजूद रहे। एसपी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि परिजनों के पास सबूत थे। उन्होंने मौके पर ही जांच अधिकारी को बुलाकर बयान दर्ज करवाए हैं। आश्वासन दिया गया है कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी।

‘सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य शीघ्र पूरा करें’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली

जयपुर, 14 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, हमारी सरकार आमजन के समग्र कल्याण के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनकल्याण से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च वरीयता देते हुए, इनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री निवास

■ **समीक्षा बैठक में ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन एवं नगरीय विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।**

पर आयोजित सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में ऊर्जा विभाग, पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, पीएचईडी, स्वायत्त शासन, जल संसाधन एवं नगरीय विकास विभाग से संबंधित विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बना कर कार्यों को शीघ्र पूरा करें।

गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभाग प्रत्येक विकास कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। उन्होंने

अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय बना कर कार्यों को शीघ्र पूरा करें, जिससे

आमजन को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुपर स्पैशिएल्टी चिकित्सा को नये आयाम देने के लिए, आरयूएचएस का उन्नयन कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इन्स्टीट्यूटयू ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) की स्थापना की जाएगी। इस केन्द्र पर आयुष विंग, वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं देने के लिए एकीकृत केन्द्र, थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक चिकित्सकीय सुविधाएं विकसित होंगी।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न 132 केवी तथा 33 केवी जीएसएस निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांसफार्मर के आस-पास के क्षेत्र में चेतानी बोर्ड लगाने के साथ-साथ, तारबंदी की जाए एवं इसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए। इसी के साथ, मुख्यमंत्री ने सांगानेर के जैन मंदिर, सांगा बाबा मंदिर तथा हनुमानजी मंदिर के आस-पास सौन्दर्यीकरण का कार्य करवाने को कहा। उन्होंने दुर्गापुरा उद्यानिकी महाविद्यालय में बालिका छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा प्रतापनगर में खेल स्टेडियम के निर्माण को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

जस्टिस गवई ने सीजेआई के पद की शपथ ली

नयी दिल्ली, 14 मई। न्यायमूर्ति बी आर गवई ने बुधवार को यहाँ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे इस वर्ष 23 नवंबर तक इस पद पर रहेंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलायी। उन्होंने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का स्थान लिया है, जो कल मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो गये। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जे पी

■ **शपथ ग्रहण कार्यक्रम में गवई के परिजन भी थे। गवई ने शपथ लेने के बाद अपनी माँ के पैर छुए।**

नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीश और कुछ पूर्व न्यायाधीश समेत, कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

इस अवसर पर न्यायमूर्ति गवई की पत्नी, मां तथा परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। शपथ ग्रहण करने के बाद, सबसे पहले उन्होंने अपनी मां के पैर छुए।

‘बलूचिस्तान ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उन ताकतों के लिए अवसर पैदा करता है जो, आपदा अवसर ढूंढती हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत इस स्थिति का गहराई से अध्ययन करेगा और फिर कोई निर्णय या कार्रवाई करेगा।।

‘कर्नल सोफिया पर टिप्पणी करने वाले को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं’

सचिन पायलट ने, ट्रंप के आतंकवाद पर एक भी शब्द नहीं कहने पर आपत्ति जताई

जयपुर, 14 मई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज बुधवार को अपने निवास पर पत्रकारों से वार्ता की। मीडिया से रूबरू होते हुए, सचिन पायलट ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कश्मीर पर दिए बयानों और कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश के मंत्री के बयानों को लेकर केन्द्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। पायलट कहा कि हमारे दोनों बहादुर योद्धा कर्नल कुरैशी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कुछ दिन पहले देश को सेना के ऑपरेशन के बारे में जिस कुशलता से जानकारी दी, उसके लिए हम सबको भारतीय होने पर उन पर फख्र है। पायलट ने कहा, जिस तरह मध्यप्रदेश के मंत्री ने टिप्पणी की, उसके बाद अब उनको मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। हमारी वीर कर्नल कुरैशी जी, जिनको तीसरी पीढ़ी फौज में काम कर रही है, उनके प्रति जो अन्याद दिखाया है, वह बिल्कुल अस्वीकार्य है।

पायलट ने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल सऊदी अरब में फिर से सीजफायर का जिक्र किया। अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापार वाला बयान बार- बार क्यों दे रहे हैं। इसको लेकर उसका सीधे तौर पर सरकार ने खंडन नहीं किया। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच शांति बढ़ाने को लेकर बात कही, उन्होंने आतंकवाद को लेकर एक शब्द नहीं कहा, पाकिस्तान आतंकवाद को पाल रहा है, उस पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तौल रहे हैं जो ठीक नहीं, भारत की तुलना चीन से होती थी, भारत की तुलना कभी भी पाकिस्तान से हो ही नहीं सकती। आश्चर्य की बात है कि ट्रंप कश्मीर मसले को बीच में ले आए, सरकार को इन तमाम सवालों



कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने निवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्यप्रदेश के मंत्री के बयानों को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है।

■ **पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आतंकवाद और सीजफायर पर संवाद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की।**

का जवाब देना चाहिए। पीओके को हमें वापस लेना है। यह प्रस्ताव संसद में दोबारा पारित किया जाए सन् 1994 में पारित इस प्रस्ताव को अब दोबारा से पारित करने का मौका है। पीओके भारत का अभिन्न अंग है। सरकार से मांग है कि चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरा देश एकजुट है।

पायलट ने कहा, भारत की तमाम जनता और राजनीतिक दल मानते हैं कि हमने बहुत आतंकी हमले झेल लिए। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ है।

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो लोन मिला , क्या उस पैसे का दुरुपयोग करके फिर से आतंक को बढ़ावा देने का काम पाक नहीं करेगा।। पाकिस्तान पर कितना विश्वास किया जा सकता है । सीजफायर के तुरंत बाद गोलाबारी हुई, कैसे विश्वास करें। आतंक को खत्म करने के मुद्दे पर भारत एक है, केन्द्र सरकार को जनता और विपक्ष का पूरा समर्थन मिला। पहलगाम के आतंकियों का क्या स्टेटस है। सेना के शीर्ष पर हम सबको गर्व है, सभी एक मत हैं। अचानक सीजफायर होना अप्रत्याशित है। सीजफायर अमेरिका द्वारा करना भी अप्रत्याशित है। उन्होंने आगे कहा कि सेना द्वारा बहुत ही सावधानी और संयम के साथ एयरस्ट्राइक की गई। इसमें किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। भारत की सेना ने फिर अपना शीर्ष दिखाया। पूरा देश सेना के साथ खड़ा है।

नाबालिग को बंधक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अभिषेकृत उसका मुंह बंद कर विधानसभा के पास एक कैफे में भी लेकर जाता और दो अन्य लड़कों से भी दुष्कर्म करता। अभियुक्त ने उसे धमकी दी कि उसका मामा पार्षद और एमएलए है। इसलिए वह किसी से नहीं डरता। रिपोर्ट में कहा गया कि 13 अगस्त को मोनू एक

अन्य लड़की को उसके कमरे में लाया था। वहीं, सुबह पुलिस आकर उस लड़की को अपने साथ ले गई। वहीं जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि होटल संचालक श्रवण सिंह ने भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। इस पर पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

एकल पट्टा प्रकरण में पूर्व आईएस संधू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
उनकी ओर से कहा गया कि टोडी रामजानीपुरा की 3.43 हेक्टर जमीन के एकल पट्टे के लिए पूर्व में जेडीए में आवेदन किया गया था। जमीन तय सीमा से अधिक होने के कारण जेडीए ने साल 2005 में प्रकरण राज्य सरकार को भेजा था, जिस पर राज्य सरकार ने पट्टा देने से इनकार कर

दिया। वहीं, साल 2009 में आवेदन होने पर जेडीए ने मामले को पुनः राज्य सरकार के समक्ष भेजा। राज्य सरकार ने साल 2011 में पट्टा जारी कर दिया। वहीं, तकनीकी कारणों के चलते साल 2013 में एकल पट्टा निरस्त कर दिया गया। संधू की ओर से कहा गया कि पट्टा निरस्त होने के बाद रामशरण सिंह ने साल 2014 में

एसीबी में शिकायत की थी। ऐसे में कोई अपराध नहीं बनता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भी एसीबी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा वापस लेने की बात कही थी। इसलिए प्रकरण के चलते कोई भी रद्द किया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकरण की सुनवाई कर रहे हैं।

सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी: मंत्री पर एफआईआर के आदेश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के महाधिवक्ता को मंत्री विजय शाह पर एफआईआर करने के आदेश दिए

जबलपुर, 14 मई। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में आपत्तिजनक बयान देने से जुड़े प्रकरण में आज राज्य के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए और कहा कि यह कार्य आज यानी बुधवार शाम तक हो जाना चाहिए। उच्च न्यायालय की युगल पीठ के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और न्यायाधीश अनुराधा शुक्ला ने इस मामले में मीडिया में आयी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को ये आदेश दिए। अदालत ने महाधिवक्ता से कहा कि इस आदेश के संबंध में तत्काल राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को अवगत कराया जाए और इसका क्रियान्वयन नहीं होने पर इस मामले में

- **कोर्ट ने बुधवार को दिन में आदेश देते हुए बुधवार शाम तक एफआईआर करने और हाईकोर्ट को रिपोर्ट करने के आदेश दिए।**
- **मंत्री विजय शाह के खिलाफ धारा 152, 196 (1) (बी) और 197 (1) (सी) के तहत एफआईआर करने के आदेश दिए। इससे मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं उनकी कुर्सी भी जा सकती है।**

अवमानना संबंधी कार्यवाही भी की जा सकती है।

अदालत ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये धाराएं देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने जैसे कृत्यों से संबंधित

वायरल हो रहा है, जो इंदौर जिले के महु विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया गया है। उसमें वे सार्वजनिक मंच से संबोधन दे रहे हैं और इस अवसर पर एक महिला नेता समेत अनेक लोग मौजूद हैं। मंत्री शाह कहते हुए सुने जा रहे हैं,जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़ थे...हमने उन्हीं की बहन भेजकर.....। मंत्री शाह इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी टोल हुए। इस मामले को भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने संज्ञान में लेने के साथ ही प्रदेश भाजपा इकाई ने मंत्री को फटकारा। इसके बाद मंत्री ने माफी भी मांगी, लेकिन मीडिया के सामने माफी मांगने संबंधी बयान के बाद उनका हंसते हुए वीडियो भी वायरल हो गया। वह वीडियो भी मंत्री की किरकिरी का कारण बन गया।

मंगलवार से उनका एक वीडियो है। अदालत के इस महत्वपूर्ण आदेश के बाद मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। माना जा रहा है कि अब राज्य पुलिस अदालत के आदेश के अनुरूप वैधानिक कदम उठाएगी। इसके साथ ही उनका मंत्री पद भी जाना तय माना जा रहा है। वे अक्सर विवादास्पद बयान देते रहते हैं।

चीन के अधिकारियों ने भारत व पाकिस्तान के राजदूतों से मीटिंग की

बीजिंग/इस्लामाबाद/नयी दिल्ली, 14 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद, चीन के शीर्ष अधिकारियों ने बीजिंग में भारतीय और पाकिस्तानी राजदूतों से अलग-अलग मुलाकात की। चीन के विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के महानिदेशक लीयू जिनसांग ने सोमवार को चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने चीन-भारत संबंधों और

■ **चीन के टॉप अफसरों ने दोनों देशों के राजदूतों से अलग-अलग बात की।**
साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मंगलवार को चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेदोंग ने पाकिस्तान के राजदूत खलील हाशमी से उनके अनुरोध पर मुलाकात की। वेदोंग और पाक राजदूत की मुलाकात में दोनों ने चीन-पाक संबंधों और क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय हालात पर चर्चा की। वेदोंग ने भारत-पाक के बीच पूर्ण और स्थायी संघर्ष-विराम का समर्थन करते हुए मतभेद सुलझाने की अपील की और क्षेत्रीय शांति में चीन की रचनात्मक भूमिका जारी रखने की बात कही।

अरब लीग ने आतंकवाद पर भारत का समर्थन किया

अरब लीग के राजदूत युसूफ मोहम्मद जमील ने एक बयान जारी कर भारत के प्रति समर्थन जताया

नयी दिल्ली, 14 मई। अरब लीग के नयी दिल्ली स्थित राजनयिक मिशन के प्रमुख युसूफ मोहम्मद जमील ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद और उखावा का खाल्ता करने के लिए भारत और अरब क्षेत्र के देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने आतंकवाद को विश्व शांति के लिए गंभीर खतरा बताया है।

राजदूत जमील ने एक बयान में कहा, देश के बाहर से संचालित आतंकवाद और ऐसे अन्य खतरों से निपटने के मामले में हमारी सोच एक जैसी है। हम खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और संयुक्त पहल के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा के वातावरण को मजबूत बनाना है।

अरब लीग के राजदूत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। उन्होंने कहा कि यह कृत्य न केवल बर्बर, बल्कि अमानवीय था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान

■ **राजदूत जमील ने एक बयान में कहा कि देश के बाहर से संचालित आतंकवाद के खतरों से निपटने के लिए हमारी सोच एक जैसी है।**

के बीच संघर्ष रकने का स्वागत किया और कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों के बीच सैनिक कार्रवाई का रुकना बहुत ही जरूरी था। जमील ने कहा, हम इस पक्ष के हैं कि दोनों देशों के बीच विवाद के समाधान के लिए बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों को अपना जाय।

ऐसा दृष्टिकोण न केवल राजनीतिक स्थिरता, बल्कि इस क्षेत्र के देशों की आर्थिक प्रगति के लिए भी आवश्यक है। जमील ने उम्मीद जताई कि अरब-भारत मंत्रीस्तरीय संचालन फोरम की एक बैठक निकट भविष्य में आयोजित की जाएगी और इससे दोनों पक्षों के बीच सहयोग को व्यापक

बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कह कि अरब लीग के देशों के साथ भारत के संबंधों को अपेक्षित गति देने के लिए इस तरह की उच्च स्तरीय सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने कहा, हमें इन बैठकों में राजनीतिक मामलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा संबंधी मामलों को भी इनमें शामिल करना चाहिए।

चीन-बांग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अदरुन्नी भूगोल के उल्लेख की ताकिकता पर सवाल खड़े किये हैं। उन्होंने कहा, “दिलचस्प बात यह है कि यूनस चीन से निवेश की सार्वजनिक रूप से अपील इस आधार पर कर रहे हैं कि (भारत के) सात उत्तर-पूर्वी राज्य लैंडलॉकड हैं। लेकिन यह कहने का आखिर औचित्य क्या है कि ये सात भारतीय राज्य लैंडलॉकड हैं?”

बुधवार को कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आरएसएस के अंदर, संकटकाल में मोदी के नेतृत्व पर गंभीर संदेह है तथा यह सोच तेजी से बढ़ती जा रही है कि वे ट्रंप का सामना नहीं कर सकते तथा संकट के समय देश को नहीं संभाल सकते। देखना यह है कि यह स्थिति वास्तव रूप लेती है, लेकिन जवाब न मिलने की स्थिति में, आक्रोश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 25 मई को एनडीए

मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई है, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुलाना और उनमें उपस्थिति होना उन्होंने उचित नहीं समझा है। एक आरएसएस समर्थक ने कहा है, “जे.पी. नड्डा हमेशा तो भाजपा अध्यक्ष पद पर रह नहीं सकते, इसलिए जब नये भाजपा अध्यक्ष की घोषणा होगी, उस समय प्रधानमंत्री मोदी के संबंध में भी कानाफूसी शुरू हो सकती है।

बिना विभागीय जाँच के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जस्टिस आनंद शर्मा ने यह आदेश नरेश पाल देवानिया की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि विभागीय जांच के बिना कर्मचारी को सेवा से हटाना अनुचित और उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिका में अधिवक्ता मोविल जीनवाल ने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 23 मार्च 2021 को छेड़छाड़ के मामले में एक एफआईआर महिला पुलिस थाना, भिवाड़ी में दर्ज हुई थी। एसपी ने बिना किसी जांच के, उसी दिन याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने इसे अपीलेट अथॉरिटी में चुनौती दी, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी

ने बिना तथ्य देखे 9 सितंबर, 2021 को उसकी अपील खारिज कर दी। इस कार्रवाई को याचिका में चुनौती दीं ते हुए कहा गया कि विभाग की कार्यवाही संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है। इसके अलावा एक सरकारी कर्मचारी को बिना सही जांच के दंडित भी नहीं किया जा सकता। मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर पीड़िता के साथ समझौता करने व उसके ही आवेदन पर निचली अदालत से रद्द हो चुकी है, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी ने इन तथ्य की अनदेखी करते हुए अपील खारिज कर दी। याचिका पर सुनवाई करते हुए अपीलकर्ता ने याचिकाकर्ता को समस्त परिलाभ सहित सेवा में लेने को कहा है।

अनिता आनन्द के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अलगाववादी एजेण्डा को बढ़ावा देने के लिए न किया जाए। यह एक नाजुक और संवेदनशील रास्ता होगा, लेकिन आनंद अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और राजनीतिक व्यवहारिकता के कारण इसे अपने पूर्ववर्तियों से बेहतर संभाल सकती है।

यदि कुशलता और परिपक्वता के साथ हैंडल किया संभाला जाए, तो उनके कार्यक्रम में रुकी हुई व्यापार वालाओं को पुनर्जीवित किया जा सकता है, प्रवासन चैनलों को फिर से खोला जा सकता है, तथा शिक्षा, टेकनॉलजी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। अनिता आनंद, प्रवासी समुदाय से जुड़े उन मुद्दों को भी गैर-राजनीतिक बनाने में मददगार हो सकती हैं, जो लंबे समय से ओंटवा और नई दिल्ली के बीच, खुली बातचीत और बातों में विश्वास की कमी के कारण जटिल होते जा रहे हैं।

तथापि, व्यापक संदर्भ को समझना आवश्यक है। कैनडा-भारत संबंधों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर लगे आरोपों के बाद पैदा हुए राजनयिक तनावों के कारण। आनंद ने एक और कैनडा की संप्रभुता और कानून के शासन को रक्षा के महत्व पर जोर दिया है, तो दूसरी ओर उन्होंने अपनी भारतीय जड़ों को भी स्वीकार किया है, जिससे उनकी विदेश

नीति में निराला और समझदारी की झलक मिलती है। फिर भी, आशाओं को यथार्थवाद के साथ जोड़कर देखना जरूरी है। प्रवासी उग्रवाद, भू-राजनीतिक मतभेद और पारस्परिक अविश्वास जैसी मूल समस्याएं एक रात में खत्म नहीं होंगी। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आनंद को कैनडा की सरकार में कितना स्वतंत्र काम करने का मौका मिलता है और नई दिल्ली कितनी गंभीरता से फिर से जुड़ने को तैयार है। यह बात स्पष्ट है कि आनंद एक नया राजनयिक चेहरा है, जो टूटो-निज्जर विवाद से अप्रभावित है। उनकी नियुक्ति कैनडा और भारत के लिए, वर्षों में पहला और संभवतः सबसे अच्छा अवसर है कि दोनों देश तनावों से आगे बढ़ें और एक व्यावहारिक, परस्पर लाभकारी साझेदारी की ओर अग्रसर हों। इस अवसर का उपयोग किया जाएगा या इसे गंवा दिया जाएगा – इससे तय होगा कि विषय के सबसे जटिल द्विपक्षीय संबंधों में से एक का भविष्य क्या होगा।

पाकिस्तान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
साथ नियमित स्तरिंग मीटिंग और अन्य संचार चैनलों के माध्यम से बीएसएफ के लगातार प्रयासों से शॉ की वापसी संभव हो पायी है।